RNI No:- DELHIN/2023/86499 **DCP Licensing Number:** F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com परिट्डन दिशिष देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित भाव से समर्पित होना पड़ेगा।

🔃 📆 सत्य की हमेशा ही होती है जीत : रविंद्र गुप्ता

🛮 🔓 जलवायु परिवर्तन का डेयरी उत्पादन पर प्रभाव

📭 महापूजा अर्चना की और सिंदुर खेला

दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा ताले लगवाए गए ८ क्षेत्रीय कार्यालयों के तालों को खुलवाने के प्रति उच्च न्यायालय में दर्ज होगी पीआईएल

संजय बाटला

नर्इ दिल्ली। टेंपल्स ऑफ़

लिबरलाइजेशन वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट की आज जनरल बाडी मीटिंग में कई सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में जो मुख्य चर्चा का विषय जिस पर सबसे अधिक समय दिया गया वह रहा परिवहन विभाग दिल्ली द्वारा बिना जनता को सूचित किए जनहित में गैजट नोटिफिकेशन द्वारा शुरू हुए 8 क्षेत्रीय कार्यालयों को तले लगवाना। इस मुद्दे पर अलग अलग बाते बैठक में सामने आई

1. परिवहन विभाग ने सरकारी खर्चीं में कटौती करने के अपनें उद्देश्य के प्रति इन्हें बंद

2. परिवहन विभाग ने राजस्व में इजाफा करवाने के अपनें उद्देश्य के प्रति इन्हे बंद

3. परिवहन विभाग द्वारा प्राईवेट कम्पनियों को इन कार्यालयों का स्थान उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इन्हे बंद किया

4. परिवहन विभाग द्वारा अपनें कर्मचारियों और अधिकारियों को कम करने के उद्देश्य से इन्हें बंद किया

5. परिवहन विभाग द्वारा दिल्ली की जनता को परेशान करवा कर बिचौलियों के माध्यम के प्रयोग के प्रति इन्हें बंद करवाया कुल मिलाकर सभी का मत यह था की

जनहित को दरिकनार कर अपनें निजी एवम सरकार के दायित्व को नजरंदाज कर दिल्ली परिवहन विभाग ने अपनें पद के बल पर इन्हे बंद किया है।

दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल की

द्वारा सहमति प्राप्त करने पर गैजट नोटिफिकेशन द्वारा जनहित में सरकारी कार्यालयों को खोला जा सकता है और इसी प्रक्रिया को पूरा करके इन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को खोला गया था पर परिवहन विभाग के आला अधिकारी ने बिना न्यायिक प्रक्रिया को अपनाए सिर्फ़ राजस्व में इजाफा करवाने और परिवहन विभाग के खर्चों में कटौती करने की इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए अपने पद के बल का प्रयोग कर बिना किसी पर्व सचना जारी किए. बिना क्षेत्रीय जनता को सचित किए, बिना उपराज्यपाल से आज्ञा प्राप्त किए 8 क्षेत्रीय कार्यालयों में ताले लगवा कर दसरे क्षेत्र के कार्यालय में विलय कर दिया। जो न्याय संगत नहीं था।

वर्ष 02, अंक 216, नई दिल्ली । मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

इस मद्दे पर सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया की जनहित में ट्रस्ट परिवहन विभाग के आला अधिकारी द्वारा ताले लगवाए गए 8 क्षेत्रीय कार्यालयों के ताले खुलवाने के लिए उच्च न्यायालय में पीआईएल दर्ज करे और इसके लिए ट्रस्ट की लीगल शाखा को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं की जल्द ही कोर्ट में पीआईएल दर्ज के लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता है उन्हे एकत्र कर पीआईएल दर्ज की जाए।

ट्रस्ट ने प्रेस विज्ञप्ति द्वारा बताया है की 15 दिन के अंदर ही हम परिवहन विभाग के द्वारा ताले लगवाए गए सभी 8 क्षेत्रीय कार्यालयों के ताले खुलवाने के प्रति उच्च न्यायालय में पीआईएल दर्ज कर ताले खुलवाने की मांग रख रहे है।



दिल्ली में हवा हुई जहरीली तो बढ़ी पाबंदियां, ग्रेप का पहला चरण लागू



दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने और वायु गुणवत्ता (AQI) खराब होने के कारण सीएक्यूएम (CAQM) की ग्रेप उप समिति ने आपात बैठक की और ग्रेप के पहले चरण की पाबंदियां लाग करने का फैसला लिया। सोमवार को दिल्ली का एक्यूआई २३४ दर्ज किया गया जो खराब श्रेणी में आता है। कई इलाकों में एक्यूआई 300 से भी ऊपर दर्ज किया गया।

नर्ड दिल्ली। हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी हो जाने एवं पराली का धआं भी दिल्ली पहंचने के साथ ही वाय गणवत्ता (Air Quality) बिगड़ने लगी है। सोमवार को लगातार दूसरे दिन भी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई, ÂQI) 200 पार 234 यानी ''खराब'' श्रेणी में पहुंच गया। दिल्ली के कई इलाकों में तो 300 से भी ऊपर ''बहुत खराब'' श्रेणी में दर्ज किया गया।

सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, एनसीआर के शहरों का भी शक्रवार को यही हाल रहा। फरीदाबाद का एक्यआई 180, गाजियाबाद का एयर इंडेक्स 271, ग्रेटर नोएडा का 274, गुरुग्राम का 108 व नोएडा का एयर इंडेक्स 268 दर्ज किया गया।

बैठक में ग्रेप के पहले चरण की पाबंदियां लाग् इसी के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम, CAQM) की ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान

(ग्रेप, GRAP) की उप समिति ने सोमवार शाम आपात

बैठक की। इस बैठक में ही ग्रेप के पहले चरण की पाबंदियों सहित 27 सूत्रीय एक्शन प्लान लागू करने की घोषणा की गई।

वायु गुणवत्ता सुधरने की थी उम्मीद

हालांकि उप समिति ने रविवार को जब एक्युआई 224 पहुंचा था, तब भी बैठक की थी और उम्मीद जताई थी कि जल्द ही यह नीचे आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दिन पहले के मुकाबले सोमवार को एक्युआई और बढ़ गया। यही स्थित बनी रहेगी. कोयले के इस्तेमाल पर रोक

उप समिति ने कहा कि पिछले 24 घंटों में वाय गणवत्ता मापदंडों में अचानक गिरावट आई है। अगले दो दिन यही स्थिति बने रहने के आसार हैं। इसमें और ज्यादा गिरावट न हो, इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रेप के पहले चरण की पाबंदियों को कड़ाई से लागू करना अनिवार्य हो गया है। इस दौरान सड़क किनारे भोजनालयों, होटलो एवं रेस्तरां में कोयले के इस्तेमाल पर पूर्णतया रोक रहेगी।

स्थानीय निकायों को दिए ये निर्देश

साथ ही वातावरण में धूल की रोकथाम के लिए स्थानीय निकायों को भी नियमित रूप से कूड़ा उठाने, सड़कों की नियमित रूप से मशीन से सफाई करने और पानी का छिडकाव करने का निर्देश दिया गया है। उप समिति ने दिल्ली और एनसीआर की एजेंसियों से सभी पाबंदियों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। साथ ही आम लोगों से भी सिटीजन चार्टर पर अमल करने का आग्रह किया है।

पुरानी गाड़ियाँ और दिल्ली सरकार का दोहरा मापदंडः सवाल उठाती एक कहानी

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 10-15 साल परानी पेटोल और डीजल गाडियों को जब्त करने का अभियान तेज कर दिया है। यह निर्देश दिल्ली परिवहन विभाग और स्थानीय आरडब्ल्यूए (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) द्वारा जारी किया गया है, जिसमें लोगों से आग्रह किया गया है कि वे ऐसी गाडियों की सूचना दें। इस पहल में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी सक्रिय रूप से शामिल है और जगह-जगह चेकिंग के दौरान पुराने वाहनों को जब्त कर रही है।

सवाल उठते हैं..

यह कदम उठाना सही है या गलत, यह तो बहस का विषय है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो उठता है वह यह है कि आखिर सरकार ने इस मुहिम की शुरुआत आम जनता से ही क्यों की ? दिल्ली के विभिन्न ट्रैफिक पिट (ट्रैफिक पुलिस के कबाड़ स्थल) में वर्षों से खड़ी सैकड़ों गाड़ियाँ क्यों नहीं उठाई गईं, जो न केवल पुरानी हो चुकी हैं, बल्कि स्थान भी घेरे हुए हैं ? ऐसे वाहन, जो 10-15 साल पुराने भी नहीं हैं, आज तक कान्नी प्रक्रिया से क्यों नहीं गुज़रे और उन्हें क्यों नहीं स्क्रैप किया गया ?

पुरानी गाड़ियों के प्रति सख्ती, पर क्या व्यवस्था की खामियां छप सकती

दिल्ली की सड़कों पर 10-15 साल पुरानी गाड़ियों को जब्त करना भले ही एक अच्छा कदम हो, लेकिन टैफिक पिट में कई सालों से खड़े वाहनों के प्रति लापरवाही प्रशासन की दोहरी नीति को उजागर करती है। जब एक आम नागरिक की गाड़ी को जब्त किया जा सकता है और उसे स्क्रैपिंग का नोटिस भेजा जा सकता है, तो फिर वर्षों से बेकार खडी सरकारी गाडियों को क्यों छोड

कायदे से देखा जाए तो, जिन गाडियों पर ट्रैफिक पिट में कई सालों से धुल जमा हो रही है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। पर वास्तविकता यह है कि इन्हें सालों से वहीं छोड़ा गया है। इस प्रक्रिया में कई बार नोटिस भेजे जाते हैं, जवाब न आने पर गाड़ियों के चालान निस्तारित होते हैं और अंततः अदालत के आदेश के बाद इन्हें ज़ब्त किया जाना चाहिए था। लेकिन इन गाड़ियों पर सरकार की कोई कार्रवाई नहीं दिखती। क्या यह अभियान सिर्फ दिखावा

यह भी विचारणीय है कि दिल्ली सरकार ने इस अभियान की शुरुआत खुद के घर से क्यों नहीं की ? सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों से पहले उन गाड़ियों का निस्तारण क्यों नहीं किया गया जो ट्रैफिक पिट में जगह घेरे हुए हैं ? सरकार की यह दोहरी नीति यह

सोचने पर मजबूर करती है कि क्या यह पूरा अभियान महज जनता को परेशानी में डालने और दिखावा करने के लिए चलाया जा रहा

दिल्ली की यह समस्या नई नहीं है। पिछले कुछ दशकों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब सरकार ने नए नियम लागू किए, लेकिन खुद उन नियमों का पालन नहीं किया। पराने वाहनों का स्क्रैपिंग अभियान पहले भी चलाया गया था, लेकिन वह भी अधरा ही रहा। इस बार सरकार ने स्पष्ट रूप से यह फैसला लिया है कि 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को राजधानी से हटाना है। लेकिन इस फैसले की आधिकारिकता तभी मानी जाएगी जब यह कानून सभी के लिए समान रूप से लागू होगा, न कि सिर्फ आम जनता के

दिल्ली में पुराने वाहनों की समस्या को हल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम प्रशंसनीय हैं. लेकिन यह तभी सार्थक हो सकते हैं जब सभी पुराने वाहनों का समान रूप से निस्तारण किया जाए। अगर सरकार आम जनता से अपेक्षा करती है कि वे अपने पुराने वाहन हटाएं, तो उसे खुद भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ट्रैफिक पिट और सरकारी संस्थानों में खड़े पुराने वाहनों का भी समय पर निस्तारण हो। वरना यह कदम महज एक दिखावा बनकर रह जाएगा और प्रदुषण की समस्या का हल नहीं निकल पाएगा।

सरकार को अपनी नीतियों की शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए, तभी जनता को विश्वास हो पाएगा कि इस अभियान का उद्देश्य सही है और यह केवल आम लोगों को परेशान करने के लिए नहीं है।

गजब मामला: पहले किया माफ, अब टैक्स मांग रहा विभाग; फिटनेस नहीं करा पा रहे टैक्सी चालकों की बढ़ी टेंशन

राजधानी दिल्ली में एक हैरान करने वाला मामला प्रकाश में सामने आया है। परिवहन विभाग ने टैक्स माफ किया और अब टैक्सी चालकों से टैक्स मांगा जा रहा है। इस वजह से हजारों टैक्सी चालक फिटनेस भी नहीं करा रहे हैं। उधर चालक भी नौकरी छोड़-छोड़कर भाग रहे हैं। जानिए आखिर टैक्स माफ करने का पूरा मामला क्या है।

नई दिल्ली। पहले खुद रोड टैक्स माफ किया था अब परिवहन विभाग टैक्सियों के मालिकों से टैक्स मांग रहा है। रोड टैक्स नहीं भरा जाने के कारण इन टैक्सियों की फिटनेस नहीं हो पा रही है। यह समस्या उन टैक्सियों के सामने आ रही है, जिनकी एक सितंबर से फिटनेस बाकी है। विभाग का कप्यूटर सिस्टम ऐसी टैक्सियों की फिटनेस करने की अनुमित नहीं दे रहा है।

दिल्ली में खड़ी हो गई 500 टैक्सी

विभाग का कहना है कि जब तक रोड टैक्स जमा नहीं होगा, टैक्सी की फिटनेस नहीं हो सकेगी। ऐसे में दिल्ली में करीब 500 टैक्सियां खड़ी हो गई हैं। बताया गया कि यह समस्या 31 अगस्त को जारी परिवहन विभाग के एक आदेश के बाद से खड़ी हो गई है, जिसमें कहा गया कि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स की छूट हटा दी गई है। मगर आदेश में इससे पहले की स्थिति के बारे में जिक्र नहीं है।

वहीं, इस आदेश के बाद से अब तक 500 इलेक्ट्रिक

टैक्सियां खड़ी हो चुकी हैं।दिन प्रतिदिन यह संख्या बढ़ रही है। दिल्ली सरकार ने 2020 में इलेक्ट्रिक वाहनों से रोड टैक्स नहीं लेने की घोषणा की थी। उसके बाद से इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स नहीं लिया गया है। इन टैक्सी वालों के पास रोड टैक्स दिए जाने का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर गत जनवरी से सब्सिडी नहीं मिल रही है। दिल्ली में 2020 से लागू हुई थी

इलेक्ट्रिक वाहन नीति

जनवरी से जून के दौरान उस समय भी लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर सब्सिडी नहीं मिल पाई है, जब दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 लागू हुई थी। जून के बाद से नीति ही समाप्त हो चुकी है। मगर इसी बीच एक उन टैक्सी वालों के सामने समस्या खड़ी हो गई है, जिन टैक्सी वालों ने दिल्ली में प्रदुषण की समस्या को देखते हुए टैक्सी में चलाने के लिए इलेक्ट्रिक कार खरीदी थी, यह बात सभी को पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक कार सीएनजी और पेट्रोल कारों से सवा गुणा से अधिक महंगी हैं, फिर भी इन लोगों ने इन्हें खरीदाँ था, अधिकतर ने कार खरीदने के लिए ऋग लिया

बता दें कि उस समय सरकार की नीति के तहत इनसे रोड टैक्स नहीं लिया गया। मगर अब परिवहन



विभाग इनकी कार की फिटनेस नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिक टैक्सी के मालिक राम कुमार कंवर कहते हैं कि पिछले एक माह से उनकी ट्रैक्सी इसलिए खड़ी है, क्योंकि टैक्सी की फिटनेस नहीं हो पा रही है। उन्होंने करीब दो साल पहले टैक्सी खरीदी थी, उस समय टैक्सी पर रोड टैक्स नहीं लिया गया था। अब विभाग रोड टैक्स जमा होने की पर्ची मांग रहा है।

आठ माह से भुगतान नहीं किया

आने वाले दिनों में सार्वजनिक परिवहन के मामले में जनता को परेशानी हो सकती है। सड़कों से 300 ई-बसें हट सकती हैं। इन बसों को चलाने के लिए पिछले आठ माह से भुगतान नहीं किया है। दिल्ली सरकार बकाया 100 करोड़ का भुगतान नहीं कर रही है। इससे बस

वालकों को वेतन तक नहीं मिल पा रहा है। कई चालक नौकरी छोड़ गए हैं। चालक अपनी समस्या बसों में सवारियों से साझा कर रहे हैं, बगैर भुगतान के कंपनी भी बसें चलाने से हाथ खड़ी कर रही हैं।

इस संबंध में दिल्ली सरकार से पक्ष मांगा या, जो उपलब्ध नहीं सका। दिल्ली सरकार ने गत फरवरी में एक साथ 300 ई-बसों को सड़कों पर उतारा था, इस बसों को एलजी वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक साथ हरी झंडी दिखाई थी। 💻 ये बसें केंद्र सरकार के तहत काम कर रही

कंपनी कंवजेंन्स एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से किए गए टेंडर के तहत जेबीएम द्वारा सड़कों पर उतारी गई थीं।

सीईएसएल इस कंपनी के माध्यम से दिल्ली में 1,500 बसें और आनी हैं। ये बसें उस समय दिल्ली को मिलीं, जब बसों की सख्त जरूरत थी। इससे कुछ समय पहले ही पुरानी होने पर दिल्ली की सड़कों से 400 बसें हटाई गई थीं।

परिवहन विभाग के अधिकारी का कहना है कि कुछ तकनीकी अड़चन है, जिसे जल्द दूर कर लिया जाएगा। जिस कारण यह समस्या सिस्टम में गड़बड़ी के कारण आ रही है। इसे दूर कर जल्द ही समस्या को सुलझाने की कोशिश की जा रही है।

<u> सिक्सधीजेविबरवा</u>झ्नेशनएंड वेबफेयएएवाइडेटुस्ट (पंजीकृत) TOLWA

website : www.tolwa.in

Email: tolwadelhi@gmail.com bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन ६० विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020) , एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय: – 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए – 4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली ११००६३ कॉरपोरेट कार्यालय :– 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स, दिल्ली के टैक्सी बसों पर लगातार होने वाले अत्याचार को लेकर दिल्ली सरकार व परिवहन मंत्रालय के खिलाफ भ्रष्टाचार का पुतला दहन करेंगे

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स, दिल्ली के टैक्सी बसों पर लगातार होने वाले अत्याचार के खिलाफ 15 अक्टूबर को दिल्ली सचिवालय पर दिल्ली सरकार और दिल्ली के परिवहन मंत्रालय और इसके दिल्ली परिवहन विभाग के खिलाफ भ्रष्टाचार का पतला दहन करेंगे.

काफी सालो से दिल्ली सरकार, उसके परिवहन मंत्रालय और दिल्ली परिवहन विभाग की तरफ से पेनिक बटन घोटाला स्पीड गवर्नर घोटाला और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट घोटाला हों रहा है, MCD टोल टैक्स (RFID टैग) घोटाला, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट घोटाला. दिल्ली में पंजीकृत टैक्सी बसों से MCD टोल टैक्स वसूली का घोटाला. प्रदूषण की आड़ में गाड़ियों को स्क्रैप (कूड़ा) बनाने का

ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट का कहना है की हम काफी

सालो से इस भर्ष्टाचार के खिलाफ आंदोलन भी कर रहें है. लेकिन दिल्ली सरकार और उसके परिवहन विभाग हमारी मांगो को अनसुना कर रहा है बल्कि पेनिक बटन जो की पेहले इनका विभाग 2019 के बाद रजिस्ट्रेड हुई टैक्सी बसों मे लगाता था अब 2019 से पेहले रजिस्ट्रेड हुई टैक्सी बसों मे भी जबरजस्ती लगवाना शरू कर दिया, अभी दिल्ली में पेनिक बटन की वजह से काफी गाड़ियाँ रजिस्ट्रेड नहीं हों रहीं है और काफी गाड़ियों का परिमट और फिटनेस नहीं हों रहीं है सबसे बड़ी बात ये है की इन पेनिक बटन के दबाने से कुछ नहीं होता. लेकिन दिल्ली के टैक्सी बसों के मालिकों को अपनी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के समय पेनिक बटन (व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस) के 10 हजार से 15 हजार हर टैक्सी बसों के लिए देने पड़ते है. बल्कि अब ये हर 2 साल की फिटनेस के समय इन डिवाइस को चेक करने के नाम पर भी 5 हजार रुपये तक लेते है, और इतना बड़ा भर्ष्टाचार निर्भया

बलात्कार के नाम पर हों रहा है. और एक तरह से ये महिलाओ का भी

मजाक बना रहें है क्योंकी ये महिलाओ की सुरक्षा के नाम भी भ्रष्टाचार कर रहें है.

आज तक दिल्ली सरकार या उसके परिवहन विभाग ने इसका कोई कॉल सेंटर नहीं बनाया, थोड़ा बहुत खाना पूर्ति के नाम पर ये गाडी की लोकेशन दिखाने की बाते ये करते है लेकिन पेनिक बटन दबाने से ना तो पुलिस आती ना ही ट्रांसपोर्ट विभाग का कोई

ऐसा ही स्पीड गवर्नर का मामला है इसमें भी करोड़ो रूपया का घपला हों चूका

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो की 200 रुपये की थी कुछ समय पेहले उसके 1000 रुपये से ज्यादा वसूल किये जा रहें है.

और ये सब दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्रालय और दिल्ली परिवहन वीभाग की मिलीभगत से इनके द्वारा कुछ प्राइवेट वेंडर द्वारा किया जा रहा है, जिस से की दिल्ली



सरकार और इसका परिवहन मंत्रालय और दिल्ली परिवहन विभाग के बड़े अधिकारी अपने को बचा सके और सारा आरोप प्राइवेट

इसी तरह दिल्ली का परिवहन विभाग प्रदूषण की आड़ में घर घर जाकर 10 से 15 साल की पेट्रोल /डीजल /सीएनजी की गाड़ियों को घर घर जाकर उठा रहा है और

अपने चहेते स्क्रैप डीलरों को गाड़ियाँ दिलवा रहा है. इसी तरह ग्रेप सिस्टम लगाकर डीजल की गाड़ियों को बंद

करवाया जा रहा है. ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट का कहना है की अगर हमारी

मांगे नहीं मानी गई तो हम आने वाले दिल्ली के चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे.

संजयसम्राट अध्यक्ष दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन.

98101821479717906644

प्रदूषण से मुक्ति

विजय गर्ग

र्चोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पराली जलाने के मुद्दे पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से जवाब तलब किया कि पराली जलाना फिर से क्यों शुरू हो गया ? सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि 'सीएक्यूएम एक्ट की धारा-14 के तहत जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कदम उठाया गया है।' अदालत ने पंजाब और हरियाणा की सरकारों को भी फटकार लगाते हुए कहा कि दोनों राज्यों ने पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की है दरअसल, सीएक्यूएम की धारा के तहत पराली जलाने पर अधिकारियों, कर्मचारियों को सजा का भी प्रावधान है। सवाल है कि क्या अकारण सर्वोच्च न्यायालय को पराली जलाने पर एक जिम्मेदार संस्थान को फटकार लगानी

क्या सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद पराली प्रबंधन विफल हो चुका है ? क्या कृषक जन-मन अब भी पूरी तरह से पराली प्रबंधन पर पुरानी परिपाटी से चल रहा है? जाहिर है, कुछ न कुछ कुप्रबंधित जरूर है। सितंबर माह के

आंकड़ों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पराली जलाने के कुल 75 मामले उजागर हो चुके हैं। हैरत की बात है कि 15-25 सितंबर के बीच पिछले वर्ष की तुलना में हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं पांच से ग्यारह फीसद तक बढ़ी हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष इसी अवधि में जहां हरियाणा में पराली जलाने के तेरह मामले पाए गए थे, इस बार बढ़ कर 70 हो गए। इसी तरह पंजाब में पराली जलाने के मामले आठ से 93 तक पहुंच गए। हरियाणा में करनाल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर सर्वाधिक प्रभावित जनपद हैं। वहां कुल 70 मामलों में 31 मामले पाए गए। इसी तरह पंजाब के कुल 93 मामलों में से 58 मामले तरनातरन, गुरुदासपुर और अमृतसर में पाए गए। अनवरत पराली दहन से बिगड़ती आबोहवा का खिमयाजा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को भुगतना पड़ता है। सर्दियों के शुरुआती दौर में ही दम घुटने-सा लगता है। अभी बीते 24 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक 203 तक दर्ज किया गया। ऐसे हालात में सुप्रीम की फटकार स्वाभाविक है। ऐसा

नहीं कि सरकार ने विगत वर्षों में पराली दहन को लेकर कुछ नहीं किया। पर शासन, प्रशासन, सरकारी संस्थाओं और पराली जलाने वाले किसानों के बीच संबंध में जरूर कुछ कमी रह जाती है। पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट के हवाले से केंद्र सरकार ने सुबे की सरकारों को पराली जलाने के दोषी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ न देने का सख्त निर्देश दिया है। पराली जलाने पर निगरानी के लिए हर वर्ष 15 सितंबर तक कंसोर्टियम फार रिसर्च आन एग्रो इकोसिस्टम मानिटरिंग ऐंड माडलिंग फ्राम स्पेस' (क्रीम्स) द्वारा सेटेलाइट से निगाह रखी जाती है। इससे 'गूगल लोकेशन' के साथ पराली जलाने का पता लग जाता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पराली जलाने पर दो एकड़ से कम क्षेत्र के लिए ढाई हजार रुपए, दो से पांच एकड़ क्षेत्र के लिए पांच हजार रुपए और पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए पंद्रह हजार रुपए तक अर्थदंड का प्रावधान किया है। दुद्वारा पराली जलाने पर संबंधित किसान के खिलाफ कारावास और अर्थदंड का भी प्रावधान है। इसी तरह धान काटने के यंत्र कंबाइन हार्वेस्टर में 'स्ट्रा मैनेजमेंट

सिस्टम' (एसएमएस) अनिवार्य कर दिया गया है। बिना एसएमएस वाले कंबाइन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। विगत वर्षों में विभिन्न सबों में हजारों किसानों के विरुद्ध पराली जलाने पर एफआइआर भी दर्ज कराई गई है। पराली जलाने से मृदा में मौजूद अनेक लाभदायक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक एक टन पराली जलने से मृदा में मौजूद 5.5 किलो ग्राम नाइट्रोजन, 2.3 किलो ग्राम फास्फोरस, 25 किलो ग्राम पोटैशियम, 1.2 किलो ग्राम सल्फर समेत अन्य उपयोगी पोषक तत्त्व नष्ट हो जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान की रपट के मुताबिक उत्तर भारत के राज्यों में पराली जलाने के कारण तकरीबन दो लाख करोड़ रुपए की आर्थिक हानि होती है। एक अन्य जानकारी के मुताबिक दिल्ली में पराली प्रदूषण की वजह से 'एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन' (एआरआइ) ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले बच्चों और बुजुगों में ज्यादा होता है। प्रदूषण का स्तर उच्च होने के कारण दिल्ली वासियों की जीवन प्रत्याशा में लगभग साढ़े छह साल की कमी आई है। पराली जलने से कार्बन

मोनो आक्साइड, कार्बन डाई आक्साइड, मीथेन, पाली सायक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन जैसी विषैली गैसें उत्सर्जित होती हैं। इन प्रदूषकों के प्रसार से 'स्माग' का एक मोटा आवरण निर्मित होता है, जिससे ब्रोंकाइटिस, तंत्रिका और हृदय संबंधी, यहां तक कि कैंसर जैसे रोगों का खतरा बढ़ जाता है। इस समस्या का समाधान केवल सरकारी तंत्र के भरोसे नहीं किया जा सकता है। इसके लिए किसानों को जागरूक बनाना होगा। किसान कम अवधि वाली धान की प्रजातियां लगाएं, जिससे पराली जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगली फसल के लिए पराली विघटन को पर्याप्त समय मिल जाए।पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने धान की सीधी बिजाई के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया था, जिससे 30 सितंबर तक वहां की मंडियों में आठ लाख टन धान बिकने आया था। इससे इतर, धान की कम अवधि वाली प्रजातियों, जैसे पीआर 126, पीबी 1509 आदि बोने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। 'हैप्पी सीडर' का प्रयोग किया जाए, जिसमें पराली का बंडल बनकर ऊपर आ जाता है, गेहूं की

बुवाई हो जाती है और पराली का बंडल पलवार के रूप में खेत पर बिछ जाता है।

इसके अलावा 'पैलेटाइजेशन' को अपनाया जा सकता है । इसमें पुआल को सुखाकर गुटिका के रूप में बदल दिया जाता है, उसे कोयले के साथ मिलाकर थर्मल पावर प्लांट और उद्योगों में ईंधन की तरह प्रयोग करते हैं। इससे एक ओर जहां कोयले की बचत होती है, वहीं दूसरी ओर कार्बन उत्सर्जन में कटौती होती है। 'गौठान' छत्तीसगढ़ का एक नवीन प्रयोग है। इसमें पांच एकड़ सरकारी भूमि में दान की गई पराली एकत्र कर गाय के गोबर और प्राकृतिक एंजाइम मिला कर जैविक खाद बनाई जाती है। पराली को 'कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट' (सीबीजीपी) में भेज दिया जाए तो ईंधन तैयार हो जाता है 1 दिल्ली के पूसा संस्थान ने 'बायो वेस्ट डिकंपोजर' तैयार किया है। इसके उपयोग से खेत में मौजूद पराली शीघ्र अपघटित होकर खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस तरह सरकारी तंत्र के अलावा सभी की समग्र संजीदगी से पराली से पार पा सकते हैं।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकारस्ट्रीटकौरचंदएमएचआर मलोटपंजाब



गुल्लकः संस्कारशालाकी एक पहल - अंकुर

स्कारशाला हमेशा से बच्चों और युवाओं में अच्छे संस्कारों को विकसित करने की दिशा में काम करती रही है। इसी प्रयास में एक पहल 'गुल्लक' शुरू की गई है, जो न केवल वित्तीय समझदारी को बढ़ावा देती है, बल्कि सामाजिक और नैतिक विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है । इस पहल का उद्देश्य बच्चों के मन में अच्छे कामों के प्रति जागरूकता लाना और उन्हें जीवन में सकारात्मक दुष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करनाहै।

गुल्लक की विशेष पहलः दो गुल्लक

इस पहल के तहत, घर में सबसे छोटे सदस्य के लिए दो गुल्लक रखने की सलाह दी

पहली गुल्लकः पैसे की गुल्लक यह गल्लक सामान्य रूप से पैसों को जमा करने के लिए होती है। बच्चे इसमें अपनी छोटी-छोटी बचतें डाल सकते हैं, चाहे वह जेब खर्च से हो या किसी विशेष अवसर पर मिले पैसों से। इससे उन्हें वित्तीय जिम्मेदारी और भविष्य की योजना बनाने की आदत विकसित होती है।

दूसरी गुल्लकः अच्छे कामों की गुल्लक दुसरी गुल्लक में हर अच्छे काम के लिए एक पर्ची डाली जाएगी।यह पर्ची किसी भी पीले रंग



हो। उदाहरण के लिए, ₹आज मैंने अपने दोस्त की मदद की₹ या ₹मैंने स्कूल के बाद अपनी पढ़ाई पूरी की ।₹ यह गुल्लक बच्चों को उनके अच्छे कार्यों का लेखा-जोखा रखने और उन्हें सराहने का अवसर देती है।

पीले रंग की स्लिप का महत्व

पीले रंग को सकारात्मकता और आशावाद का प्रतीक माना जाता है। जब भी बच्चा कोई अच्छा काम करता है, वह एक पीले रंगकीस्लिपपर उसकामकाविवरणलिखता है और गुल्लक में डालता है। यह प्रक्रिया न केवल उसे अच्छे कामों के प्रति जागरूक

बनाती है, बल्कि हर बार उसे प्रेरित भी करती है कि वह अपने जीवन में और भी सकारात्मक

कदम उठाए। सकारात्मकदृष्टिकोणकी शक्ति

गुल्लक की इस पहल का सबसे बड़ा उद्देश्य बच्चों को सकारात्मक दुष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करना है। जब वे नियमित रूप से अपने अच्छे कामों को लिखकर गुल्लक में जमा करते हैं, तो इससे उनकी आत्म-विश्वास में वृद्धि होती है। वे महसूस करते हैं कि उनके छोटे-छोटे अच्छे काम भी उनके जीवन में बड़ी सकारात्मकता ला सकते हैं।

यह प्रक्रिया उन्हें यह सिखाती है कि जीवन

में सिर्फ पैसे जमा करना ही महत्वपूर्ण नहीं है. बल्कि अच्छे कामों का भी अपना एक मुल्य है। धीरे-धीरे, बच्चा यह समझने लगता है कि सच्ची संपत्ति केवल वित्तीय रूप से नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक रूप से भी अर्जित की

परोपकार की दिशा में पहला कदम

गुल्लक की यह पहल न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए हैं, बल्कि इसे परोपकार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा सकता है। जब बच्चे यह समझते हैं कि उनका हर अच्छा काम समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो वे स्वाभाविक रूप से परोपकार के कार्यों की ओर आकर्षित होते हैं।

हर बच्चे को इस पहल से यह सिखने का मौका मिलेगा कि परोपकार केवल बड़े कार्यों का नाम नहीं है। छोटे-छोटे अच्छे काम भी समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह पहल उन्हें यह सिखाती है कि दान केवल पैसों से नहीं, बल्कि अपने अच्छे कर्मों से भी किया जा सकता है।

गुल्लक की यह पहल संस्कारशाला के माध्यम से बच्चों और युवाओं को नैतिकता, सकारात्मकता और परोपकार की दिशा में एक सशक्त कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। यह न केवल उनके जीवन को समृद्धबनाती है. बल्कि समाज के लिए भी एक बेहतर भविष्य का निर्माण करती है।

पर्यावरण पाढशालाः घर की सुंदरता और शुद्ध वायु के लिए सबसे बेहतरीन इंडोर पौधे :- अंकुर



3 मधुनिक जीवनशैली के कारण आजकल हममें से अधिकतर लोग ज्यादातर समय घर के अंदर बिताते हैं।

ऐसे में, यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपने घर के अंदर की वायु को शुद्ध बनाए रखें। इंडोर पौधे न केवल हमारे घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि वायु को भी शुद्ध करते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे पौधों के बारे में जो न केवल दिखने में सुंदर हैं, बल्कि प्राकृतिक एयर प्यूरीफायर का भी काम करते हैं।

1. ऐरेका पाम (Areca Palm) ऐरेका पाम एक संदर और हरा-भरा पौधा है जो घर की सजावट में चार चाँद लगाता है। यह



पौधा वायु को शुद्ध करने के साथ-साथ ऑक्सीजन का भी अच्छा स्रोत है। इसे हल्की धूप और नियमित पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे खिड़की के पास रखा जा सकता

2. स्नेक प्लांट (Snake Plant) स्नेक प्लांट, जिसे 'मदर-इन-लॉज टंग' भी कहा जाता है, एक ऐसा पौधा है जो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन, फॉर्मल्डीहाइड जैसे हानिकारक रसायनों को अवशोषित करता है। इसे ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती. इसलिए यह व्यस्त जीवनशैली के लिए एक



मनी प्लांट को भाग्यशाली पौधे के रूप में

जाना जाता है और यह घर के किसी भी कोने में

जहरीली गैसों को दूर करता है और घर की नमी

आसानी से उगाया जा सकता है और इसे प्रत्यक्ष

को भी बनाए रखता है। इसे पानी या मिट्टी में

लगाया जा सकता है। यह वायु में मौजूद

4. एलोवेरा (Aloe Vera)

करने वाला पौधा भी है। यह हवा से

एलोवेरा न केवल स्वास्थ्य के लिए

फायदेमंद है बल्कि यह एक बेहतरीन वायु शुद्ध

धूप की आवश्यकता नहीं होती।

आदर्श पौधा है।

फॉर्मल्डीहाइड और बेंजीन जैसे रसायनों को हटाने में सक्षम है। एलोवेरा को कम पानी और 3.मनीप्लांट (Money Plant)

> खिड़की के पास रखा जा सकता है। 5.स्पाइडरप्लांट(Spider Plant) स्पाइडर प्लांट उन पौधों में से एक है जो हवा में मौजूद लगभग 90% हानिकारक रसायनों को हटाने में मदद करता है। यह खासतौर पर बच्चों और पालतू जानवरों वाले घरों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह जहरीला नहीं होता। इसे सीधी धुप की आवश्यकता नहीं होती और यह तेजी से

सीधी धूप की जरूरत होती है, इसलिए इसे

बढने वाला पौधा है। 6.पीसलिली (Peace Lily)







पानी देना होता है और अप्रत्यक्ष धूप में रखना चाहिए। 7. बैंबू पाम (Bamboo Palm)

अवशोषित करता है। इसे सप्ताह में एक बार

ट्राइक्लोरोइथाइलीन जैसी हानिकारक गैसों को

फॉर्मल्डीहाइड, बेंजीन, और

बैंबू पाम भी एक प्रभावी एयर प्यूरीफायर है। जो घर के अंदर की हवा को शुद्ध करता है। यह वायु में मौजुद कार्बन मोनोऑक्साइड और फॉर्मल्डीहाइंड को कम करता है। इसे नियमित पानी की जरूरत होती है और इसे हल्की छाया में

रखना चाहिए।

इन इंडोर पौधों के माध्यम से हम न केवल अपने घर की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं, बल्कि घर के अंदर की वायु गुणवत्ता को भी सुधार सकते हैं। पौधों की देखभाल करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि उन्हें सही मात्रा में पानी, प्रकाश, और पोषण मिले। पौधे न केवल हमारे जीवन को हरियाली से भरते हैं बल्कि हमें शुद्ध और ताजगी से भरी हवा भी प्रदान करते हैं।

आइए, पर्यावरण पाठशाला के इस संदेश को अपनाते हुए अपने घर को इन प्राकृतिक एयर प्यरीफायर के साथ सजाएँ और स्वस्थ जीवनशैली की ओर कदम बढ़ाएँ।

वाई श्रेणी की सुरक्षा होने के बावजूद महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष के नेता बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या कर दी गई- संजय सिंह

नर्ड दिल्ली।भाजपा शासित राज्यों में लगातार बढ रही आपराधिक घटनाओं पर आम आदमी पार्टी ने तीखा हमला बोला है। वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा कि भाजपा की सरकारें अपराध और अपराधियों को काबू करने में परी तरह से नाकाम हैं।जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, वहां अपराध चरम पर है। सरेआम हत्या, लूट और महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है। इसका ताजा उदाहरण महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष के नेता बाबा सिद्दीकी की सरेआम की गई हत्या है, जबकि उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा भी मिली हुई थी। वहीं, दिल्ली में सरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की है इसके बाद भी ग्रेटर कैलाश में जिम मालिक की हत्या हो गई। संजय सिंह ने कहा कि अगर भाजपा की सरकारों ने समय रहते सतर्कता नहीं दिखाई, तो आने वाले दिनों में और भी ऐसी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं।

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि पूरे देश में जहां-जहां भाजपा का शासन है, वहां अपराध चरम पर



हैं। हत्या, लूट, अपहरण और गैंगरेप की घटनाएं लगातार हो रही हैं। व्यापारियों पर फायरिंग और वसुली की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इसके बावजूद, भाजपा की केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारें इन अपराधों पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह विफल साबित हुई

www.newsparivahan.com

हैं। ताजा मामला विजयादशमी के दिन महाराष्ट्र में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का है। वह महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री थे और उनका बेटा वर्तमान में वहां विधायक है। बाबा सिद्दीकी विपक्ष के नेता नहीं थे, बल्कि एनसीपी अजीत पवार गट से सत्ता पक्ष के नेता थे। उन्हें वाई श्रेणी की सरक्षा मिली हुई थी. इसके बावजद उनकी सरेआम हत्या कर दी गई।

उन्होंने कहा कि इसी तरह दिल्ली में एक जिम मालिक की हत्या कर दी गई। करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई। पंजाबी गायक सिद्ध मुसेवाला की हत्या कर दी गई। लॉरेंस बिश्नोई नाम का गैंगस्टर पूरे देश में अपना गैंग चला रहा है। वह खुलेआम धमकी देता है और फिर मर्डर हो जाता है। पुलिस कुछ नहीं कर पाती। दिल्ली में, जहां केंद्र सरकार बैठी हुई है और यहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की है, वहीं ग्रेटर कैलाश में एक जिम मालिक की हत्या हो गई। इसमें भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया। यहां तक कि बाबा सिद्दीकी, सिद्धू मूसेवाला और करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया है। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल में बैठकर पूरे देश में अपना गैंग चला रहा है, लेकिन पुलिस और भाजपा की सरकारें कुछ नहीं कर पा रही हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा के पक्ष में ट्वीट

करने वाले लोग जिन्हें खुद प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर फालो करते हैं। वो लोग ऐसी घटनाओं की निंदा करने की बजाय इन घटनाओं के पक्ष में लिख रहे हैं। यानि इन घटनाओं को भाजपा का पुरा बैकअप मिला है। इससे साबित होता है कि भाजपा इन्हें संरक्षण दे रही है। बाबा सिद्धिकी की हत्या कोई मामूली घटना नहीं है। मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र की जनता आने वाले चुनाव में भाजपा और शिंदे सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। हैरान करने वाली बात है कि जिस व्यक्ति को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है उसकी हत्या हो जा रही है। देश की राजधानी में हत्या हो जा रही है।

संजय सिंह ने आगे कहा कि एक व्यक्ति खुलेआम देश में गैंग संचालित कर रहा है। और उसने कई और लोगों को भी धमकियां दी हैं। अगर भाजपा की सरकार ने समय रहते सतर्कता नहीं दिखाई, तो आने वाले दिनों में और भी ऐसी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए, यदि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों में जरा भी शर्म बाकी है, तो उन्हें तुरंत सचेत होकर ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

मदरसों से संबद्ध एनसीपीसीआर की सिफारिश अनुचित: मर्कज़ी तालीमी बोर्ड सचिव





सुषमा रानी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा 11 अक्टूबर को जारी परिपत्र के जवाब में, मर्कज़ी तालीमी बोर्ड (एमटीबी) के सचिव सैयद तनवीर अहमद ने मदरसों के अनुचित चित्रण और इन संस्थानों को निशाना बनाने वाली आधारहीन सिफारिशों पर आपत्ति व्यक्त की। मीडिया को जारी एक बयान में, एमटीबी सचिव ने कहा, ₹एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो द्वारा भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजा गया परिपत्र मुस्लिम बच्चों की शिक्षा में मदरसों की भूमिका को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है और कई भ्रामक दावे करता है। एनसीपीसीआर का तर्क है कि मदरसों को शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 से छट देने से बच्चों को गणवत्तापर्ण शिक्षा तक समान पहुंच से वंचित होना पड़ेगा। हालांकि, यह इस तथ्य की अनदेखी करता है कि केवल 4% मुस्लिम छात्र मदरसों में जाते हैं, जैसा कि सच्चर सिमित ने उजागर किया है, जबिक 96% मुख्यधारा के शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित हैं।इसके अलावा मदरसे आधुनिक शिक्षा का विरोध नहीं करते हैं - कई मदरसे पहले से ही धर्मशास्त्र के साथ-साथ विज्ञान, गणित, कंप्यूटर और भाषाएं पढ़ाते हैं। भारत भर के प्रमुख विश्वविद्यालय धर्मशास्त्र में पाठुयक्रम प्रदान करते हैं, और धार्मिक अध्ययन को शामिल करने को वंचना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। एनसीपीसीआर परिपत्र में वित्तीय सहायता बंद करने की सिफारिश की गई है, तथा कहा गया है कि मदरसे आरटीई प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं. भले ही वे बोर्ड से संबद्ध हों या यूडीआईएसई कोड रखते हों।

सत्य की हमेशा ही होती है जीत: रविंद्र गुप्ता



परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली: दिल्ली के पंजाबी बाग में भी लेजर शो के माध्यम से संपूर्ण रामायण की प्रस्तुति की गई । इसके बाद बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक रावण दहन किया गया।

इस मौके पर दशहरा कमेटी पंजाबी बाग के प्रधान रविंद्र गप्ता ने बताया कि राजधानी दिल्ली के पंजाबी बाग में दशकों पुराने श्री दशहरा कमेटी पंजाबी बाग में रावण दहन से पहले लोगों के बीच भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का संदेश पहुंचाने के मकसद से सुंदर झांकियां निकाली गई। यह झांकी पंजाबी बाग की विभिन्न इलाको से होती हुई निकाली गई, जिसमें बच्चों के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय

लोगों की भी भागीदारी देखने को मिली। पूरा इलाका राम की भक्ति में डूबा नजर आया। इस दौरान श्री राम, लक्षण, सीता, रावण और रामायण के अलग अलग किरदारों के माध्यम से एक संदेश देने का

कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार सहित भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और कई हिंदूवादी लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के आयोजकों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों के अंदर अभी से ही हिंदू धर्म के प्रति जागरूकता पैदा होगी। साथ ही बच्चों को मयार्दा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शो पर चलने की प्रेरणा मिलेगी।

विश्वभर के कलाकारों, विद्वानों और नृत्य आलोचकों को एक मंच पर लाने वाला अनोखा महोत्सव

नई दिल्ली : भारत की राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, 16 से 21 अक्टूबर 2024 तक पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन करेगी। छह दिवसीय इस महोत्सव में विभिन्न देशों के कलाकार, विद्वान, नृत्य आलोचक और प्रदर्शनकारी शामिल होंगे। महोत्सव का उद्देश्य कलाकारों के लिए स्थायी करियर के अवसरों पर विचार-विमर्श करना, नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना, और प्रदर्शनकारी कला के लिए संस्थागत समर्थन को बढ़ावा देना है।

महोत्सव का उद्घाटन समारोह 16 अक्टूबर को ए.पी. शिंदे संगोष्ठी भवन, एनएएससी कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली में आयोजित होगा, जिसमें संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्य अतिथि होंगे। अन्य विशिष्ट अतिथियों में हेमा मालिनी, लोकसभा सदस्य (मथुरा), पद्मविभूषण डॉ. पद्मा सुब्रमण्यम, पद्म विभूषण डॉ. राजा और राधा रेड्डी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. संतिश्री धूलिपुडी पंडित, और माननीय लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, मणिपुर के राज्यपाल शामिल होंगे।

इस महोत्सव में पद्म विभूषण, पद्म भूषण, और पद्म श्री सम्मानित कलाकारों द्वारा संचालित 30 सत्रों का आयोजन होगा। ये सत्र भारतीय नृत्य की ऐतिहासिक और समकालीन प्रगति, नृत्य शिक्षा में प्रशिक्षण पद्धतियों, और प्रदर्शनकारी कलाओं के शोध-पद्धतियों पर केंद्रित होंगे।

इन चर्चाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का परियोजनाओं का समर्थन, और कलाकारों के लिए



आर्थिक मॉडल पर भी चर्चा की जाएगी।

विशेषज्ञ और नीति-निर्माता कोरियोग्राफी. शोध, और फिल्म-उद्योग से संबंधित करियर विकल्पों पर भी विचार करेंगे ताकि कला जगत में संतुलित और स्थायी वातावरण बनाया जा सके।

हर शाम कमानी ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ आयोजित होंगी, जिनमें डॉ. सोनल मानसिंह और रामली इब्राहिम जैसे प्रसिद्ध कलाकारों की प्रस्तुतियाँ होंगी। इन प्रस्तुतियों में भारतीय और विदेशी कलाकारों की प्रतिभा का प्रदर्शन होगा, जिससे दर्शक एक समृद्ध सांस्कृतिक अनुभव प्राप्त करेंगे।

इसके साथ ही, महोत्सव में दो प्रमुख प्रदर्शनियाँ भी आयोजित की जाएँगी। पहली प्रदर्शनी ललित कला अकादमी, रवींद्र भवन में होगी, जिसमें संगीत नाटक अकादमी के ऐतिहासिक योगदान को दर्शाया जाएगा। दसरी प्रदर्शनी ए.पी. शिंदे संगोष्ठी भवन में आयोजित होगी, जिसमें महोत्सव में भाग लेने वाले कलाकारों और प्रस्तुतकर्ताओं की उपलब्धियों को प्रदर्शित

महोत्सव के उद्देश्यों पर बात करते हुए, संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष डॉ. संध्या पुरेचा ने

कहा, ₹कलाकारों को लंबे समय से आर्थिक चनौतियों, सीमित संस्थागत समर्थन, और बदलती आर्थिक परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस महोत्सव के माध्यम से, हम इन चुनौतियों का समाधान करने और युवा नृत्यकारों के लिए नए अवसर पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि पारंपरिक नृत्य-रूप आज की तेज़ी से बदलती दुनिया में भी प्रासंगिक बने रहें।"

डॉ. पुरेचा ने आगे कहा, ₹यह महोत्सव केवल कलाकारों का जमावड़ा नहीं है, बल्कि उद्यमियों, सरकारी अधिकारियों, विद्वानों, शोधकर्ताओं और छात्रों को एक मंच पर लाने का प्रयास है। हम कला के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे और नीतिगत सझाव तैयार करेंगे. जो भारत की कला और संस्कृति के भविष्य को आकार देंगे।"

संगीत नाटक अकादमी के सचिव राजू दास ने महोत्सव के महत्व पर जोर देते हुए कहा, ₹यह महोत्सव केवल प्रस्तृतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मंच है जहाँ कलाकार मिलकर अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और स्थायी समाधान खोज सकते हैं। यह अनुठा आयोजन प्रदर्शनकारी कलाओं को सशक्त बनाने की दिशा

युवा भागीदारी और सांस्कृतिक विविधता को बढावा

महोत्सव में युवाओं की भागीदारी को विशेष महत्वदिया गया है और भारतीय प्रवासी समुदाय से भी सहयोग की उम्मीद की जा रही है। यह आयोजन विद्वानों, कलाकारों और प्रदर्शनकारियों के विविध प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करेगा और भारत की समृद्ध लोक, जनजातीय, और समकालीन नृत्य परंपराओं को उजागर करेगा।

कला जगत के स्थायी भविष्य की ओर एक कदम : यह अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव 1958 में आयोजित ऐतिहासिक संगोष्ठी की विरासत को आगे बढ़ाता है, जिसे संगीत नाटक अकादमी ने आयोजित किया था। यह महोत्सव केवल कला का उत्सव नहीं है, बल्कि स्थिरता, सशक्तिकरण, और नीतिगत समर्थन पर संवाद के लिए एक मंच भी है। इन चर्चाओं और प्रस्तुतियों के माध्यम से, महोत्सव प्रदर्शनकारी कलाओं के लिए एक समर्थनकारी वातावरण तैयार करने का प्रयास करेगा, जिससे कलाकारों को उनकी कला के लिए पहचान, फंडिंग, और अवसर मिल सकें।

संगीत नाटक अकादमी के बारे में:भारत की राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और नाटक अकादमी – भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी है। इसे भारत सरकार के (तत्कालीन) शिक्षा मंत्रालय के 31 मई 1952 के एक प्रस्ताव के तहत स्थापित किया गया था। अकादमी ने अगले वर्ष से कार्य करना शुरू किया, जब डॉ. पी.वी. राजमन्नार को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया और इसकी अखिल भारतीय प्रतिनिधि परिषद, यानी महासभा का गठन हुआ।

सेन्ट जोहन एम्बुलेंस ब्रिगेड दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी दिल्ली के सहायक आयुक्त पी ड़ी वर्खिया के आदेशानुसार नवरात्रि मेला कालकाजी मन्दिर, एवं युवा रामलीला कमेटी गोविन्द पुरी फ़र्स्ट ऐड पोस्ट लगाई

दक्षिण पर्वी दिल्ली : सेन्ट जोहन एम्बलेंस ब्रिगेड दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी दिल्ली के सहायक आयक्त श्री पी डी वर्खिया के आदेशानसार नवरात्रि मेला कालकाजी मन्दिर ,एवं युवा रामलीला कमेटी गोविन्द परी फ़र्स्ट ऐड पोस्ट लगाई हैं।

प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट आयोजको के आग्रह पर 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक लगाई गई हैं क्योंकि जो आयोजन हो रहा है उनमें कभी भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। जिससे निपटने के लिये फ़र्स्ट एड पोस्ट लगवाई जाती है। कालकाजी मन्दिर पर 24 घण्टे फ़र्स्ट एड पोस्ट लगाई गई है।

सभी फ़र्स्ट एड पोस्ट कोर्प्स ऑफिसर श्रीमती मोनिका कशवाहा जी के मार्गदर्शन में क्रमशः सेवा में हैं। इस दौरान कालकाजी मन्दिर पर करीब 600 दर्शनार्थियों को प्राथमिक चिकित्सा सेवा प्रदान की गई साथ ही रामलीला गोविन्द पुरी में करीब 200 दर्शकों को प्राथमिक सहायता प्रदान की गई।

कालकाजी मन्दिर। मॉर्निंग शिफ्ट।

- 01 श्री चन्दन एम्बलेंस ऑफिसर। 02श्री ओमवीर एम्बुलेंस मैम्बर।
- 03 कुमारी विशाखा नर्सिंग मैम्बर।
- 04 कुमारी राखी नर्सिंग मैम्बर। 05 श्रीमती खुशबू नर्सिंग मैम्बर।
- दोपहर की शिफ्ट। 01 श्री प्रेम चंद सार्जेंट।
- 02 श्री यस सार्जेंट।
- 03 कुमारी झिलमिल नर्सिंग मैम्बर । 04 कुमारी खुशबू नर्सिंग मैम्बर । रात्रिशिफ्ट 8 से 3.
- 01 सुमित कुमार सिंह पोस्ट इंचार्ज।
- 02 श्री कुनाल एम्बुलेंस मैम्बर। 03 मोहम्मद कामरा एम्बुलेंस मैम्बर।





सुबह 3.30 से 8 बजे तक। 01 श्री विनोद एम्बुलेंस मैम्बर। 02 श्री प्रदीप कुमार एम्बुलेंस मैम्बर । श्री युवा रामलीला कमेटी गोविन्द पुरी कालकाजी नई दिल्ली।

01 श्रीमती मोनिका कुशवाहा कोर्प्स ऑफिसर। 02 कमारी तनन डिवीजन कमांडर। ०३ श्री यस सार्जेंट।







सेन्ट जोहन एम्बुलेंस ब्रिगेड दक्षिणी दिल्ली के सहायक आयुक्त श्री पी डी वर्खिया के आर्दशानुसार

अम्बेडकर नगर सेक्टर पांच नई दिल्ली के तहत श्री शिव शक्ति रामलीला कमेटी एवं मेला विराट मैदान दक्षिण पुरी । में श्री योगेश कुमार कोर्प्स कमांडर के मार्गदर्शन में







निम्नलिरिवत अधिकारियों ने अपनी सेवाएं दी। ०१ श्री दिलीय कमार डिविजनल कमांडर । ०१ कुमारी प्रीति वरिर्वया नर्सिंग सार्जेंट । ०३ श्रीमती माधुरी नर्सिंग सार्जेंट । ०४ श्रीमती सञ्जन नर्सिंग सार्जेंट । ०३ अक्टूबर २०१४ से १४ अक्तूबर २०१४ तक करीब ५०० दर्शकों को प्राथमिक चिकित्सा सेवा दी गई। जिसकी मेला कमेटी ने भी सराहना की ।

इंडियन मेन्स वियर ब्रांड 'तस्वा' के 'बारात बाय तस्वा' में रणबीर कपूर उतरे रैम्प पर

दिल्ली: शादी, प्रत्येक भारतीय परिवार के लिए सबसे महत्वपर्ण और शानदार आयोजन होता है। ऐसे में इस दौरान कपड़ों से लेकर स्टाइल तक पर काफी ध्यान दिया जाता है। आज के दौर की डिजाइनर शादी के लिए खूबसूरत व डिजाइनर परिधानों के शानदार प्रदर्शन के लिए आदित्य बिड़ला फैशन रिटेल लिमिटेड द्वारा 'तस्वा' ने दिग्गज फैशन डिजाइनर तरुण तहिलियानी के साथ मिलकर एक अविस्मरणीय फैशन शो 'बारात' का आयोजन किया, जिसमें तस्वा ने अपने ऑटम/विंटर 2024 वेडिंग कलेक्शन का अनावरण किया। यह भव्य कार्यक्रम रविवार, 13 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली के राजसी त्रावणकोर पैलेस में हुआ। खास बात यह कि इस स्पेशल फैशन शो की अमिट छाप इसमें शामिल होने वाले सभी लोगों पर विशेष रूप से देखी गई। शाम का नाटकीय समापन बॉलीवुड आइकन रणबीर कपूर की अगुआई में हुआ, जिन्होंने बेजोड़ शैली और भव्यता के साथ भारतीय शादियों के सार का जश्न मनाया। दरअसल, तस्वा द्वारा 'बारात' जीवंत और जीवंत भारतीय शादी के जुलूस से प्रेरित थी, जिसेएक फैशन शोकेस के रूप में दुबारा तैयार किया गया था, जिसमें दूल्हे को दिखाया गया था। बारात, जो पारंपरिक रूप से दुल्हे के हर्षोल्लास के आगमन का प्रतीक है, को इस अपारंपरिक और अत्यंत आकर्षक फैशन शो में प्रस्तृत किया गया।

अपनी बेदाग शैली और करिश्मे के लिए मशहूर रणबीर कपूर ने शानदार भारतीय शादी-शैली की बारात के साथ शो का समापन किया, जो शाम का मुख्य आकर्षण बन गया। रणबीर कपूर इस फैशन इवेंट में फेमस डिजाइनर तरुण तहिलियानी के लिए शो स्टॉपर भी बने। रणबीर कपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह दूल्हा बने नजर आ रहे हैं। उनका यह वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है। वीडियो में रणबीर बारात और ढोल-नगाड़ों के साथ ग्रैंड एंट्री लेते नजर आ रहे हैं। वीडियो में रणबीर कपुर आइवरी और ब्लश पिंक शेरवानी और दुपट्टा लिए नजर आ रहे हैं और सिर पर पगड़ी



पहने हुए हैं। उन्होंने पिंक कलर की मोजरी भी पहन रखी हैं। वीडियो में रणबीर कार में बारात के साथ ग्रैंड एंटी लेते नजर आते हैं। जैसे ही वह रैंप पर आते हैं, सभी उनके साथ डांस करने लगते हैं और रणबीर भी सबका साथ देते हैं।

इस फैशन शो में अपनी भागीदारी के बारे में रणबीर कपूर ने बताया, 'बारात कलेक्शन में रनवे पर कदम रखना एक रोमांचक अनुभव था, जो परंपरा और आधुनिक स्वभाव के मिश्रण का जश्न मनाता है! आज के दुल्हे समारोह का हिस्सा भर नहीं हैं, बल्कि वे कहानी का दिल हैं। इस संग्रह ने उन्हें अपनी जड़ों का सम्मान करते हुए अपनी व्यक्तिगत पहचान को व्यक्त करने का अवसर दिया। अपनी शानदार बनावट और बोल्ड सिल्हट के साथ यह मेन्सवियर को फिर से परिभाषित करता है और सनिश्चित करता है कि हर दुल्हे की यात्रा अविस्मरणीय हो !'

रणबीर के अलावा, रनवे पर कई बेहतरीन व्यक्तित्वों का एक पूरा लाइनअप था, जिन्होंने इस इवेंट में अपना अनुठा आकर्षण और स्टाइल भर दिया। उभरते सितारे विहान समत, मशहर कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी, मिशेलिन स्टार शेफ सुवीर सरन और लोकप्रिय डिजिटल इन्फ्लुएंसर, मोहक नारंग, मानव छाबड़ा, उन्नति मल्हारकर और अपूर्वा (जिन्हें 'द रिबेल किड' के नाम से भी जाना जाता है) ने तस्वा के असाधारण वेडिंग कलेक्शन को एक अलग शान और अंदाज के साथ पेश किया।

अतिक्रमण हटाने के बाद इंदिराप्रम क्षेत्र

की ग्रीन बेल्ट को संवारने के लिए भी नगर

निगम ने विशेष कार्य योजना तैयार की है।

विक्रमादित्य सिंह मलिक

नगर आयुक्त, गाजियाबाद

गाजियाबाद में दिवाली के बाद गरजेगा बुलडोजर, नगर निगम के निशाने पर आया ये पाँश इलाका

गाजियाबाद नगर निगम एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसके लिए योजना तैयार की जा रही है। इंदिरापुरम में ग्रीन बेल्ट को कब्जा मुक्त कराने के लिए दिवाली बाद अभियान चलाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को मौके से हटाया जाएगा। इसके बाद इंदिरापुरम क्षेत्र की ग्रीन बेल्ट को संवारा जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने खास योजना तैयार की है।

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद। इंदिरापुरम में ग्रीन बेल्ट को कब्जा मुक्त कराने के लिए नगर निगम अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। दिवाली के बाद नगर निगम की टीम इंदिरापुरम क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट को कब्जा मुक्त कराएगी।

अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को मौके से हटाया जाएगा। दरअसल, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) से नगर निगम को इंदिरापुरम हस्तांतरण की कार्रवाई पूरी होने के बाद अब नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्य कराने की

एस्टीमेट तैयार करने में जुटे अधिकारी

नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मिलक के निर्देशानुसार निगम के सभी विभागों के अधिकारी एस्टीमेट तैयार करने में जुटे हैं। एक महीने में टेंडर का आवंटन कर विकास कार्य शुरू करा दिए जाएंगे। इसके अलावा इंदिरापुरम क्षेत्र की ग्रीन बेल्ट को संवारने के लिए भी निगम ने विशेष कार्य योजना तैयार की है।

निगम के उद्यान प्रभारी डॉक्टर अनुज सिंह ने बताया कि दिवाली के बाद इंदिरापुरम क्षेत्र की ग्रीन बेल्ट को पूरी कर अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। साथ ही पौधे रोपित करने के लिए अभियान

होम कंपोस्टिंग के लिए लोगों को



जागरूक कर रहा निगम

नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मिलक के निर्देश पर नगर निगम होम कंपोस्टिंग को लेकर शहरवासियों को जागरूक कर रहा है। डोर-टू-डोर स्वच्छ भारत मिशन की टीम के सदस्य जाकर हर घर स्वच्छता, हर घर हरियाली का नारा दे रही हैं। हर नागरिक को गाजियाबाद नगर निगम कचरा अलग-अलग करने के लिए भी जागरूक कर रहा है। निगम के पांचों जोन यह अभियान चलाया जा

हरियाली को बढ़ावा देने की अपील नगर आयुक्त ने बताया कि शहरवासियों से गीले कचरे से खाद बनाकर अपने घर की बॉलकनी, गार्डन व अन्य स्थानों पर लगे हुए पौधों में खाद का उपयोग किए जाने के लिए अपील की जा रही है। इस प्रक्रिया से न केवल घर के कचरे का निस्तारण हो रहा है बल्कि हरियाली को भी बढावा मिल रहा है। शहरवासियों को हर घर को

स्वच्छता और हरियाली के लिए जागरूक किया जा रहा है। एक हजार लोगों ने अपनाई होम

<mark>कंपोस्टिंग</mark> गोले करारे से किस प्रकार खाद बनाई जा

गीले कचरे से किस प्रकार खाद बनाई जा सकती है और खाद का इस्तेमाल किस प्रकार अपने गार्डन में किया जा सकता है। शहरवासियों को इसकी विस्तार से जानकारी दी जा रही है। मालूम हो कि गाजियाबाद नगर निगम सीमा में एक हजार नागरिकों द्वारा अब तक होम कंपोस्टिंग को अपनाया गया है। निगम का प्रयास इस कवायद में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोडने का है।

ग्रेटर नोएडा वालों के लिए अच्छी खबर, यीडा 2024 में ही शुरू कर देगा ये सुविधाएं

ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए अच्छी खबर है। YEIDA ने सेक्टरों में मूलभूत सुविधाओं की कमी को दूर करने का फैसला किया है। दिसंबर के अंत तक सीवर पानी और बिजली जैसी सुविधाएं शुरू हो जाएंगी। प्राधिकरण ने परियोजना विभाग को 31 दिसंबर तक का समय दिया है। इस साल के अंत तक आवंटियों को सेक्टर में पानी बिजली और सीवर कनेक्शन आदि की समस्याओं से निजात मिल जाएगी।

ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के लोगों की समस्याओं का समाधान इसी साल हो जाएगा। यमुना प्राधिकरण इसे लेकर गंभीर है और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं।

बताया गया कि यमुना प्राधिकरण Yamuna Authority के सेक्टरों में दिसंबर अंत की मूलभूत सुविधाओं का अभाव दूर हो जाएगा।सीवर, पानी व बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं सेक्टरों में शुरू हो जाएंगी।

अड़चन को दूर करने के निर्देश टिए

प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डा. अरुणवीर सिंह ने C Writtling uniform anyon tweedered affections follower withour en

परियोजना विभाग को अभियान चलाकर सेक्टरों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में आ रही अड़चन को दर करने के निर्देश दिए हैं।

सेक्टरों में मूलभूत सुविधाओं का टोटा

यमुना प्राधिकरण के आवासीय सेक्टर 18, 20 व 22 डी, 16, 17 में भूखंड वनिर्मित भवन परियोजनाएं हैं। सेक्टर में भूखंडों की लीज होने के बाद आवंटियों ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। सौ से अधिक भवन बनकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन लोग इनमें बसने को तैयार नहीं है, इसकी वजह सेक्टरों में मूलभूत सुविधाओं का टोटा

परियोजना विभाग को 31 दिसंबरतककावक्तदिया

वहीं, सुरक्षा से लेकर पानी, सीवर जैसी सुविधाएं मिलने में अड़चन है। पानी की लाइन बिछी होने के बावजूद कनेक्शान नहीं जारी हुए हैं। सीवर कनेक्शान व बिजली कनेक्शन में भी अड़चन है। इस समस्याओं को दूर करने के लिए सीईओ ने परियोजना विभाग को 31 दिसंबर तक का वक्त टिगाडै।

परियोजना विभाग के प्रभारी को दिएगएनिर्देश

परियोजना विभाग के प्रभारी महा प्रबंधक एवं ओएसडी राजेश कुमार को निर्देश दिए हैं कि साल के अंत तक अंतिम प्वाइंट तक पानी की आपूर्ति पहुंच जाए। सड़क, बिजली लाइन का काम पूरा करने और सीवर कनेक्शन के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। सीईओ का कहना है कि

इसी साल में समस्याओं का समाधान कराने की कोशिश

साल के अंत तक आवंटियों को सेक्टर में पानी, बिजली एवं सीवर कनेक्शन आदि की समस्याएं दूर हो जाएंगी। जल निकाली के लिए भी परियोजना विभाग को उचित बंदोबस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राधिकरण की कोशिश है कि लोगों को ऐसी सुविधाएं मिले ताकि वह अपने निर्मित भवन में आकर रहें। वहीं, ऐसे में माना जा रहा है कि यमुना प्राधिकरण के निर्देश के बाद इसी साल सभी समस्याओं तो दूर कर लिया जाएगा। अगर इसी साल समस्याओं का समाधान हो जाता है तो भवनों के मालिकों को सीधा फायदा मिलेगा।

राशन कार्ड की लिस्ट से कटा १० हजार लोगों का नाम, पकड़े गए फर्जी दस्तावेज; अपात्रों पर कार्रवाई जारी

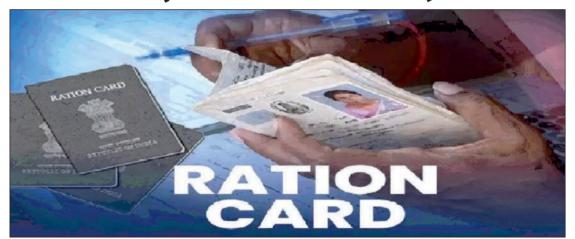
अगर आप अपात्र होते हुए राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं तो जल्द ही आपका नाम लाभार्थियों की सूची से कट सकता है। गाजियाबाद में मुफ्त राशन पाने वाले 10000 अपात्र लोगों के नाम राशन कार्ड सूची से हटा दिए गए हैं। सत्यापन में 30000 लोग अपात्र पाए गए थे। ई-केवाईसी न कराने पर भी राशन कार्ड निरस्त होगा।

गाजियाबाद। अपात्र होते हुए भी मुफ्त राशन का लाभ ले रहे दस हजार लोगों का नाम पात्रता सूची से काट दिया गया है। इन लोगों के स्थान पर जो पात्र लोग अब तक राशन कार्ड न बनने से परेशान थे, उनका नाम पात्रता की सूची में जोड़ा गया है। गाजियाबाद जिले में 20 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त राशन का लाभ दिया जा रहा था।

सत्यापन में 30 हजार लोग मिले

सरकार द्वारा लाभार्थियों का सत्यापन कराया गया तो पता चला कि 30 हजार लोग अपात्र हैं। इन अपात्रों का जिले स्तर पर सत्यापन करने के निर्देश दिए गए थे।

जिला पूर्ति विभाग द्वारा सत्यापन के बाद दस हजार लोगों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया गया है। सत्यापन अभी भी जारी है, ऐसे में इस महीने के अंत तक कई अन्य लोगों के नाम भी लाभार्थियों की सूची से हटाए जाएंगे।



ई-केवाइसी न कराने पर भी निरस्त होगा राशन कार्ड

जिले में सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाइसी कराना अनिवार्य किया गया है। अब तक 63 प्रतिशत लोगों ने ही ई-केवाइसी कराया है। जिन लोगों ने ई-केवाइसी नहीं कराया है, उनको राशन डीलर के माध्यम से ई-केवाइसी कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है, यदि जल्द ही ई-केवाइसी नहीं कराया तो उनका राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा।

इसे लेकर जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि सत्यापन के दौरान जो राशन कार्ड धारक योजना के लिए अपात्र मिल रहे हैं, उनके राशन कार्ड को निरस्त किया जा रहा है। सत्यापन का कार्य अभी जारी है। कब तक है ई-केवाईसी की लास्ट टेट?

सरकार ने राशन कार्डधारकों के लिए राहत दी है। अब कार्डधारक दिसंबर तक ई-केवाईसी करा सकेंगे। इसके पहले यह समयसीमा सितंबर तक थी। आप अपने आधार कार्ड और लिंक किए गए मोबाइल नंबर का उपयोग करके आसानी से अपने राशन कार्ड की केवाईसी को ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं है।

ऐसे करें ऑनलाइन केवाईसी आवश्यक दस्तावेज एकत्र करें। सुनिश्चित करें कि आपके पास अपना आधार कार्ड, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड हो।

खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

इसके बाद ईकेवाईसी विकल्प ढूंढ़ें और उस पर क्लिक करें।

अपना राशन कार्ड नंबर और 12 अंकों का

आधार नंबर दर्ज करें। ओटीपी सत्यापित करें- आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए ओटीपी

किसान आंदोलन के नाम पर हुए बवाल का जो सच सामने आया है उससे देश को सतर्क हो जाना चाहिए

जाहिर है कांग्रेस पार्टी गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयान से किनारा ही करेगी लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि किसानों के नाम पर खड़ा किया गया आंदोलन पूरी तरह राजनीतिक था और इसका एकमात्र मकसद मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करना था।

नीरज कुमार दुबे श ने हाल के कुछ वर्षों में कई 🕻 आंदोलन देखे। सबसे पहले जन लोकपाल के लिए आंदोलन हुआ। इस आंदोलन को मिले समर्थन के बलबुते अरविंद के जरीवाल सत्ता की सीढ़ियां चढ़ कर अपनी मंजिल पर पहुँच गये लेकिन दिल्ली में जन लोकपाल नहीं बनाया। देश ने दिल्ली में हरियाणा के कुछ पहलवानों का आंदोलन भी देखा। यह पहलवान राजनीति के अखाड़े में कूदने के लिए उसी खेल को नुकसान पहुँचाते रहे जिसकी बदौलत उन्होंने दौलत और शोहरत कमाई। देश ने किसान आंदोलन भी देखा। किसानों के कल्याण और उनके बेहतर भविष्य के लिए मोदी सरकार जो तीन कानून लेकर आई उसके बारे में भ्रम फैला कर देशभर में किसानों का आंदोलन खड़ा कर दिया गया जिसके चलते सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। ख़ुद को किसान कहने वाले आंदोलनकारियों ने कानून व्यवस्था का भी खुब मजाक बनायां और सरकार को झुकाने का अभियान सफलतापूर्वक चलाकर

दिखाया। मगर अब इस किसान आंदोलन का सच एक प्रमुख आंदोलनकारी ने ही देश के सामने रख दिया है।

हम आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के चढ़नी गुट के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़नी ने कहा है कि किसानों ने हरियाणा में कोंग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया था। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक गुरनाम सिंह चढ़नी ने कहा है कि किसानों ने हरियाणा में कोंग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया था, लेकिन पार्टी ने सब कुछ वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर छोड़ दिया था। संयक्त संघर्ष पार्टी के संस्थापक चढ़नी ने विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण यही बताया है। चढ़नी के बयान पर सियासत भी शुरू हो गयी है और भाजपा ने कांग्रेस से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण की मांग भी की है। जाहिर है कांग्रेस चढ़नी के बयान से किनारा ही करेगी लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि किसानों के नाम पर खड़ा किया गया आंदोलन पूरी तरह राजनीतिक था और इसका एकमात्र मकसद मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करना था। समय-समय पर इस आंदोलन से जड़े तमाम सच सामने आते ही रहे हैं। टूलिकट गैंग के सदस्यों ने भोले भाले किसानों को बरगला कर अपने राजनीतिक हित तो साध लिये मगर अन्नदाता का नुकसान करवा दिया।

आम किसानों का कैसे अपने राजनीतिक हितों के लिए इन तथाकथित किसान नेताओं ने दुरुपयोग किया यह हमने लोकसभा चुनावों के दौरान भी देखा था। तीनों कृषि कानून काफी पहले ही यानि साल 2022 के अंत में ही वापस लिये जा चुके थे लेकिन उसके बावजूद 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान पंजाब में भाजपा के सभी उम्मीदवारों के



घर के बाहर बड़ी संख्या में किसानों को धरने पर बैठा दिया गया था । पंजाब में चुनाव प्रचार की कवरेज के दौरान जब मैंने संगरूर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला आदि क्षेत्रों में धरने पर बैठे लोगों से पछा कि आपकी मांगें क्या हैं तो सबका जवाब एक ही था कि सारी समस्याओं के हल तक हम यहां से नहीं हटेंगे। जब मैंने पुछा कि समस्याएं क्या हैं तो हर जगह से यही जवाब मिला कि स्कूल अच्छे बनने चाहिए, अस्पतालों में सारी सुविधाएं होनी चाहिए, सड़कें अच्छी बननी चाहिए। स्पष्ट था कि यह धरना प्रदर्शन भी एक टूलिकट का हिस्सा था। लोकसभा चुनावों के लिए मतदान होते ही यह प्रदर्शनकारी भाजपा उम्मीदवारों के घर के बाहर से हट गये।ऐसा लगा कि उनकी सारी समस्याओं का या तो समाधान हो गया है या टूलिकट के तहत दिया गया टास्क पूरा

वैसे जहां तक चढ़नी की बात है तो आपको बता दें कि उन्होंने हरियाणा में कुरुक्षेत्र की पेहोवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। यहां जनता ने मात्र 1170 वोट देकर उनकी जमानत तक जब्त करा दी। हम आपको यह भी याद दिला दें कि इन तथाकथित किसान नेताओं ने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों में भी किस्मत आजमाई थी। पंजाब की 31 में से 22 किसान यूनियनों ने संयुक्त समाज मोर्चा नामक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा था और किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी घोषित किया था। लेकिन एक को छोड़कर इनके बाकी उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाये थे। अब हरियाणा में भी इस पार्टी का जो हश्र हुआ है उससे साफ है कि आम जनता और आम किसानों का समर्थन इन लोगों के पास कभी भी नहीं था। विदेशी इशारे पर और विदेशी पैसे के

बलबूते भारत की छवि को खराब करने और सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का जो षड्यंत्र रचा गया था उसका सच सामने आ चुका है। यह समय है कि देश सतर्क हो जाये और गैर-राजनीतिक आंदोलनों की असली मंशा को पहचाने।

बहरहाल, चढ़ूनी के बयान पर हमलावर होते हुए भाजपा ने कहा है कि जिस किसान आंदोलन को सहज और स्वाभाविक बताया गया था, वह दरअसल कांग्रेस की ओर से 'प्रायोजित और पोषित' था। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि चढ़ूनीजी का जो वक्तव्य आया है, उसने एक बार फिर उजागर कर दिया है कि कांग्रेस की जमीन के अंदर क्या छुपा हुआ है। उन्होंने कहा है कि इससे एक बात बहुत साफ हो गई है कि जिस आंदोलन को सहज और स्वाभाविक आंदोलन कहा जा रहा था, वह कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित और पोषित आंदोलन था।

गाजियाबाद में घर बसाने का मौका GDA की नई टाउनशिप का काम हुआ शुरू

गाजियाबाद में आशियाना बसाना चाह रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने हरनंदी पुरम टाउनशिप पर काम शुरू कर दिया है। जीडीए ड्रोन सर्वे से स्थायी और अस्थायी निर्माण का आकलन कर रहा है। योजना को परवान चढ़ाने के लिए खाली जमीन देखी जा रही है। 16 अक्टूबर को टेंडर खोले जाएंगे। इसके बाद किसानों से जमीन खरीदी जाएगी।

गाजियाबाद।हरनंदी पुरम टाउनशिप विकसित करने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने स्थायी और अस्थायी निर्माण आंकना शुरू कर दिया है। इसके बाद किए गए निर्माण को माना जाएगा। जीडीए सचिव इस योजना को परवान चढ़ाने के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए हैं।

बनाए गए हैं। ड्रोन कराया गया भूमि का सर्वे: हरनंदी पुरम टाउनशिप को विकसित करने के लिए जीडीए वीसी अतुल वत्स ने प्लानिंग कर इसको धरातल पर उतारने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इसके तहत ड्रोन सर्वे कराकर चिह्नित भूमि का सर्वे कराया जा चुका है। इब इसका ड्रोन से ही स्थायी और अस्थायी निर्माण के अलावा खाली पड़ी भूमि को भी देखा जा रहा है।

16 अक्टूबर को खोले जाएंगे टेंडर : इस जमीन को चिह्नित कर रिपोर्ट तैयार होगी। फिर यदि कोई इस जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। योजना को आगे बढ़ाने के लिए अब प्राधिकरण ने टेंडर निकाले हैं, जो 16 अक्टूबर को खोले

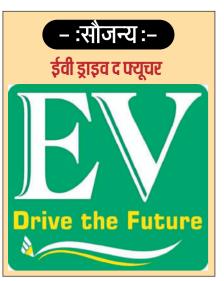
टाउनशिप के नोडल अधिकारी जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि शासन की मंजूरी मिलने के बाद टाउनशिप के लिए जमीन की दर का निर्धारित की जाएगी।भूमि अधिग्रहण के लिए पहले धारा 11 का कार्य किया जाएगा।

किसानों से जमीन खरीदेगा प्राधिकरण: इसके बाद उस क्षेत्र में कोई जमीन की खरीद फरोख्त नहीं कर सकेगा। प्राधिकरण किसानों के साथ वार्ता कर जमीन खरीदेगा। जमीन की कीमत तय करने के लिए डीएम की अध्यक्षता में बनी कमेटी के समक्ष प्रस्ताव भेजा जाएगा।

कम आबादी वाले 55 गांवों की तस्वीरमें भरे जारहे 'विकास केरंग'

जब गाजियाबाद जिले के विकास की बात की जाती है सबसे पहले गांवों की तस्वीर देखी जाती है। जिले 55 गांवों को आदर्श बनाने के लिए चिह्नित किया गया है। यह गांव कूड़ा निस्तारण और पानी की बचत करने में अव्वल बन जाएंगे।

इन गांवों में कूड़ा संग्रहण व पृथकीकरण, नाली, सोख्ता गड्ढा, सेनेटरी इंग्रुवमेंट, सीमेंट के डस्टिबन, कूड़ा वाहन, कंपोस्ट पिट, सामुदायिक कंपोस्ट पिट, स्वच्छता किट, एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि काम बराए जा रहे हैं। यह काम तेजी से चल रहा है। हालांकि 100 गांवों में पहले से यह काम चल रहा है।



वज्रम इलेक्ट्रिक ने ईवी उत्पादन क्षमताओं का विस्तार करने के लिए वर्कास ऑटोमोबाइल्स में 40% की हिस्सेदारी



परिवहन विशेष न्यूज

ईबाइकगो की सहायक कंपनी वज्रम इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने हैदराबाद स्थित इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता वर्कास ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड में 40% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। इस अधिग्रहण का उद्देश्य भारत के इलेक्टिक वाहन बाजार में वज्रम की उपस्थिति को

वर्कास ऑटोमोबाइल्स ने 25,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन डिलीवर किए हैं और ₹110 करोड का राजस्व अर्जित किया है, जो इसकी विकास क्षमता को दर्शाता है। कंपनी ने

कहा कि वज्रम और वर्कास के बीच साझेदारी से तालमेल बनाने की उम्मीद है जो भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नवाचार में सुधार और उत्पादन बढ़ा सकता है।

इस अधिग्रहण के साथ, वज्रम इलेक्ट्रिक का इरादा वर्कास की विनिर्माण क्षमताओं का लाभ उठाकर उत्पादन को बढ़ाना है, खास तौर पर टियर-2 और टियर-3 शहरों में।भारतीय ईवी बाजार में उल्लेखनीय वद्धि हो रही है, जो सरकारी पहलों और टिकाऊ परिवहन में उपभोक्ताओं की बढ़ती रुचि से प्रेरित है

वज्रम की विस्तारित क्षमता उसे उभरते बाजार की जरूरतों को परा करने में मदद कर सकती है।

वज्रम इलेक्ट्रिक लिमिटेड के चेयरमैन डॉ. इरफान खान ने कहा कि यह साझेदारी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बढ़ती मांग को परा करने के लिए आवश्यक परिचालन पैमाने और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करेगी। इस सहयोग का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और किफायती इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक सलभ बनाना है, जिससे भारत में हरित गतिशीलता को बढावा देने में योगदान मिलेगा।

टाटा का नैनो ईवी का सपना रहा अधूरा

रतन टाटा ने अपने औद्योगिक साम्राज्य में टेटली चाय से लेकर जगुआर लैंड रोवर और एयर इंडिया को जोड़कर अपने लगभग सभी सपने पूरे किए। टाटा नैनो का इलेक्ट्रिक संस्करण लाने का उनका सपना अधुरा ही रहा। टाटा ने कोयंबत्तुर की कंपनी जयम औंटोमोटिव्स को इस कॉन्सेप्ट कार पर काम करने की जिम्मेदारी सौंपी थी और लगभग 400 कार उतारे जाने के बावजूद कोविड-19 और नए क्रैश नियमों के चलते इसे सडक पर उतारने का सपना परा नहीं हो सका।

ओला के संस्थापक भवीश अग्रवाल टाटा को अपना हीरो मानते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर टाटा की इस ड्रीम परियोजना को याद किया। टाटा इस परियोजना को लेकर इतने उत्साहित थे कि वह खुद ही अग्रवाल को कोयंबत्तर ले गए थे ताकि उन्हें अपनी इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना की एक झलक दिखा सकें और उन्होंने टेस्ट ट्रैक पर कार भी ड्राइव की। बाद में इससे ही प्रेरित होकर अग्रवाल ने ओला इलेक्ट्रिक की शुरुआत की।

अग्रवाल ने उन्हें याद करते हुए लिखा, 'वर्ष 2017 में एक दिन मुझे उनका फोन आया और उन्होंने मुझे मुंबई आने के लिए कहा। उन्होंने कहा भवीश मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूं और कुछ रोमांचित करने वाली चीज दिखाना चाहता हूं। हम टाटा नैनो से इलेक्ट्रिक वाहन बनाने की उनकी निजी परियोजना देखने उनके विमान से ही कोयंबत्तर गए। वह इलेक्टिक वाहनों को लेकर बेहद भावुक और उत्साहित थे। वह मुझे एक टेस्ट ड्राइव पर भी लेकर गए और इंजीनियरों को इसमें व्यापक स्तर पर सुधार करने की ताकीद भी दी। यही वह दिन था जिस दिन मूल रूप से ओला इलेक्ट्रिक की शुरुआत हुई।'

वर्ष 2015 में टाटा ने कम लागत वाली ईवी बनाने के बारे में सोचा, जिससे नियो ईवी की शुरुआत हुई। इस पर जयम और टाटा समूह ने संयक्त रूप से काम किया। जयम नियो ईवी या कुछ लोग इसे इलेक्ट्रिक टाटा नैनो भी कहते हैं को संयुक्त रूप से कोयंबत्त्र की इंजीनियरिंग एवं प्रोडक्शन कंपनी जयम और टाटा ने तैयार किया था जिस पर सेवामुक्त चेयरमैन रतन टाटा

निजी तौर पर नजर रख रहे थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस गाड़ी के दो संस्करण लाने की योजना थी जिसमें से एक 48 वोल्ट वाला संस्करण और दूसरा 72 वोल्ट वाला ताकतवर संस्करण शामिल था। इस परियोजना ने वर्ष 2018 में रफ्तार पकड़ी जब जयम ने 400 कारें तैयार की और इसकी आपूर्ति ओला कैब को

इन कारों का इस्तेमाल महामारी के दौर की शुरुआत में हैदराबाद और बेंगलुरु में किया गया था। जयम ऑटो के प्रबंध निदेशक जे आनंद ने कहा, 'मैं ईवी परियोजना के बारे में बात नहीं करना चाहता। हमें एक ऐसी परियोजना पर चर्चा क्यों करनी चाहिए जो कई सरकारी नियमन के कारण सफल नहीं हो पाई? कोविड-19 और नए क्रैश नियमन से परियोजना का विस्तार प्रभावित हुआ। हालांकि हमारे रिश्ते अब भी समूह के साथ अच्छे हैं।'

मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि नियो ईवी को कई कारकों की वजह से कभी भी बिक्री के लिए पेश नहीं किया गया जिनमें से एक वजह यह भी थी कि इंजीनियर 72 वोल्ट वाले संस्करण की लागत कम करने की कोशिश में जुटे थे।

महामारी के अलावा क्रैश परीक्षण के सख्त नियमों ने भी इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डालने में योगदान दिया। फिलहाल जयम ऑटो, आनंद की कंपनी और चेन्नई की कंपनी मुरुगप्पा समृह प्रवर्तित ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया

(टीआईआई) के बीच समान भागीदारी वाला संयुक्त उद्यम है। अपनी सहायक कंपनी टीआई क्लीन मोबिलिटी के जरिये टीआईआई ने पिछले साल जयम ऑटो में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी

फिलहाल जयम ऑटो, इलेक्टिक वाहनों में पूरी विशेषज्ञता के साथ वाहनों के कलपुर्जे, इसकी प्रणाली और प्रोटोटाइप के डिजाइन, परीक्षण और निर्माण से जुड़ा हुआ है। आनंद ने कहा कि उसकी इस परियोजना पर फिर से नए सिरे से काम करने की कोई योजना नहीं है। रतन टाटा के निधन के बाद हम केवल उम्मीद ही कर सकते हैं कि उनकी कम लागत वाली ईवी का सपना एक दिन साकार हो जिसकी बेहतर बॉडी और एयरबैग हो और जो नई सुरक्षा आवश्यकताओं को भी पूरा करे।

20% तक पहुंच जाए तो ईवी सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का सही समय: सियाम अध्यक्ष

परिवहन विशेष न्यूज

सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नवनिर्वाचित अध्यक्ष शैलेश चंद्रा के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों के लिए सरकार की मांग सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का सही समय तब है, जब किसी विशेष वाहन श्रेणी में प्रवेश 20% तक पहुंच जाए।

उनका मानना है कि सरकारी सब्सिडी तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक कि पर्याप्त संख्या में लोग किसी विशेष वाहन श्रेणी में प्रौद्योगिकी का अनुभव नहीं कर लेते तथा इसके बारे में सकारात्मक प्रचार नहीं कर लेते।

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्राज ने कहा, ₹यह निश्चित रूप से अनुमान है कि बढते पैमाने और इन प्रौद्योगिकियों की लागत संरचना में कुछ कटौती के साथ यह उस स्तर तक नीचे आ जाएगी कि सब्सिडी समाप्त की जा

उन्होंने कहा कि सेल की लागत में कमी, स्थानीयकरण और बढ़ते पैमाने के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत में कमी आ रही है। हालांकि पहले भी व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक कारों को मांग सब्सिडी नहीं मिलती थी, लेकिन चंद्रा ने कहा कि इलेक्ट्रिक कारों की कीमत में कमी आ रही है, जो आईसी इंजन वाहनों के काफी करीब है।

उन्होंने कहा, रजब पहुंच 20% तक पहुंच जाएगी, तो सब्सिडी कम करना शुरू करने का सही

सियाम अध्यक्ष की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब सरकार वित्तीय वर्ष 2027 से इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों की खरीद पर मांग प्रोत्साहन को समाप्त करने की संभावना है। वर्तमान में इलेक्टिक वाहनों के लिए मांग प्रोत्साहन पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत दिए जाते हैं, जिसे 1 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था।

पीएम ई-ड्राइव में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर के लिए ईएमपीएस में दी गई सब्सिडी का



स्तर जारी रहेगा. लेकिन इसके दूसरे साल में इन दोनों सेगमेंट के लिए प्रति वाहन सब्सिडी आधी हो जाएगी। फेम II स्कीम की तुलना में ईएमपीएस में भी सब्सिडी कम की गई थी। इस बीच सरकार ने नई सब्सिडी स्कीम में इलेक्ट्रिक ट्रक और एंबुलेंस को भी शामिल किया है।

चंद्रा ने बताया. ₹यह सिर्फ़ अनभवजन्य है. क्योंकि हमने उन देशों में देखा है जहाँ ईवी को सफलता के रूप में देखा जाता है। आमतौर पर, जब आप उस तरह की पहुंच बना लेते हैं, तो आप सब्सिडी खत्म करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए, चीन। क्योंकि तब पाँच में से एक व्यक्ति ईवी खरीदता है और फिर सकारात्मक बातें फैलाता है और बाकी लोगों को प्रभावित करता है। संभवतः यही वह मोड हो सकता है।

बेड़े के लिए इलेक्ट्रिक यात्री कारों को पहले सरकार की फेम 1 और फेम 2 योजनाओं में शामिल किया गया था. जबकि ईएमपीएस और पीएम ई-ड्राइव में इस सेगमेंट को शामिल नहीं किया गया था। निजी इलेक्ट्रिक कारों को कभी भी कोई मांग सब्सिडी

पीएम ई-ड्राइव योजना से इलेक्ट्रिक कारों को बाहर रखने के बारे में पूछे जाने पर चंद्रा ने कहा कि पर्याप्त चार्जिंग बुनियादी ढांचे की कमी इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में बड़ी बाधा है और पीएम ई-ड्राइव का यात्री वाहन चार्जिंग बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने से इसे और अधिक अपनाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

नहीं चलेगी मनमानी को लेकर इलेक्ट्रिक स्कूटर के बाद अब कैब सर्विस पर भी सरकार की सख्त नजर

परिवहन विशेष न्यूज

ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर और सीईओ भाविश अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। इलेक्ट्रिक स्कटर के बाद अब ओला कैब्स पर भी सरकार सख्ती से नजर रख रही है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने कैब सर्विस देने वाली कंपनी ओला को कंज्यूमर फ्रेंडली बदलाव लाग करने का निर्देश दिया है। इसमें रिफंड के ऑप्शन देना और 'ऑटो राइड' के लिए रसीदें देना शामिल है। सीसीपीए ने रविवार, 13 अक्टूबर को ये जानकारी दी।

उपभोक्ता मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मताबिक सीसीपीए ने पाया कि जब भी कस्टमर्स ने ओला ऐप पर कोई शिकायत दर्ज की तो कंपनी ने बिना सवाल-जवाब वाली रिफंड नीति के तहत केवल एक कूपन कोड प्रदान दे देता था, जो सिर्फ अगली राइड इस्तेमाल किया जा सकता था। यानी कस्टमर्स को यह ऑप्शन ही नहीं मिलता था कि वह रिफंड अकांउट में चाहता है या कुपन कोड के रूप में।

कंपनी की यह पॉलिसी उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि रिफंड का मतलब यह नहीं हो सकता है कि कंपनी कस्टमर्स को दूसरी सवारी के लिए मजबर करे।

चीफ कमिश्नर निधि खरे के नेतृत्व में सीसीपीए ने पाया कि ओला की रिफंड पॉलिसी में सिर्फ भविष्य की राइड के लिए कूपन कोड दिए गए थे, जबिक ग्राहकों को बैंक अकाउंट में रिफंड का ऑप्शन नहीं दिया गया था। सीसीपीए ने एक बयान में कहा, ''ये चलन उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करता है।'' नियामक ने कहा कि बिना सवाल पूछे रिफंड नीति का मतलब ये नहीं हो सकता कि कंपनी लोगों को सिर्फ अगली बार सर्विस लेने के लिए इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करें। सीसीपीए ने ओला को अपने प्लेटफॉर्म के जरिए बुक की गई सभी 'ऑटो राइड' के लिए बिल जारी करने का भी आदेश दिया है।

बताते चलें कि इससे पहले सीसीपीए ने भाविश अग्रवाल की कंपनी ओला इलेक्टिक को



नोटिस जारी किया था। इलेक्ट्रिक टु-व्हीलर बनाने वाली कंपनी ओला के खिलाफ एक साल में क्वालिटी और पोस्ट-सेल्स सर्विस से जुड़ी 10,000 से ज्यादा शिकायतें मिली थीं। इन शिकायतों का समाधान नहीं होने के बाद सीसीपीए ने ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई शरू करते हुए 7 अक्टबर को कारण

बताओ नोटिस जारी किया था। सीसीपीए ने ओला इलेक्टिक को नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिनों का समय दिया है।

नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) को पिछले एक साल से ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ 10,000 से ज्यादा शिकायतें मिली थीं। समाधान के लिए इन शिकायतों को कंपनी के

हाई कमान तक भेजा गया. लेकिन कंपनी ने इन शिकायतों का समाधान करने में वो दिलचस्पी

नहीं दिखाई, जो उन्हें दिखानी चाहिए थी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2 (47) के अनुसार, 'अनुचित व्यापार व्यवहार का अर्थ है ऐसा व्यापार व्यवहार, जो किसी भी वस्तु की बिक्री, उपयोग या सप्लाई को बढावा देने या किसी भी सेवा के प्रावधान के उद्देश्य से किसी भी अनचित तरीके या अनचित या भ्रामक व्यवहार को अपनाता है। इसमें (vii) बेचे गए सामान या प्रदान की गई सेवाओं के लिए ऐसे बिल या रसीद जारी नहीं करना जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है

सोलर पैनल और ईवी चार्जिंग के लिए नहीं करना पड़ेगा डबल खर्चा

नोएडा में बिजली निगम अपने उपभोक्ताओं को अच्छी बिजली सप्लाई को लेकर लगातार कार्य कर रहा है। इसी क्रम में बिजली निगम उपभोक्ताओं को एक और सहुलियत दी है। उपभोक्ताओं को सोलर पैनल और ईवी वाहन चार्जिंग के लिए अलग-अलग मीटर लगाने पड़ते हैं, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिजली निगम द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए लगाए स्मार्ट मीटर में अब दोनों सुविधाएं

अभी सोलर पैनल कनेक्शन लगवाने के बाद अलग से मीटर लगाना पड़ता है। मीटर का खर्च भी उपभोक्ताओं को ही देना पड़ता है। इसके अलावा ईवी वाहनों को चार्ज करने के लिए अलग से मीटर लगाना पड़ता है,

जिसका भार भी उपभोक्ताओं को ही उठाना पडता है। इससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। ऐसी समस्याओं से निपटने और उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बिजली निगम स्मार्ट मीटर लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।फिलहाल योजना के तहत इस स्मार्ट मीटर का शल्क भी उपभोक्ताओं से नहीं लिया जा

सोलर पैनल से अतिरिक्त बिजली बिजली निगम को दी जाती है। जरूरत पड़ने पर उसे वापस भी लिया जा सकेगा। स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ता को सोलर पैनल और ईवी वाहन के लिए अलग से मीटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उपभोक्ताओं को इस स्मार्ट मीटर में ही सारी सुविधाएं मिल जाएंगी।



अतुल ग्रीनटेक ने ई-मोबिलिटी समाधान में सुधार के लिए जियो प्लेटफॉर्म्स के साथ की साझेदारी

परिवहन विशेष न्यूज

अतुल ऑटो लिमिटेड की सहायक कंपनी अतुल ग्रीनटेक प्राइवेट लिमिटेड ने इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में नवाचार और डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड (जियो) के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग का उद्देश्य अतुल ग्रीनटेक की दक्षिण अमेरिका, यूरोपीय संघ, पर्वी अफ्रीका और भारत सहित बाजारों में ईवी और ई-मोबिलिटी समाधान देने की क्षमता में सुधार करना है।

यह साझेदारी जियो की IoT मोबिलिटी तकनीक का लाभ उठाएगी, जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कनेक्टिविटी को जोड़ती है ताकि उपयोगकर्ताओं के लिए वास्तविक समय के टेलीमैटिक्स डेटा और बेहतर विश्वसनीयता प्रदान की जा सके। अतुल ग्रीनटेक वैश्वक स्तर पर बी2बी और बी2सी दोनों क्षेत्रों के लिए अपनी सेवाओं

को बढ़ाने के लिए जियो के चार्जिंग समाधान, ऑटोमोटिव क्लस्टर. टेलीमैटिक्स हार्डवेयर और प्लेटफ़ॉर्म और अंतर्राष्ट्रीय एम2एम कनेक्टिविटी को एकीकृत करेगा। इससे स्थानीय सोर्सिंग में सुधार, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और डेटा उपयोग को अनुकृलित करने, चार्जिंग समय को कम करने और बेडे के ऑपरेटरों के साथ-साथ अंतिम उपयोगकर्ताओं को लाभ होने की उम्मीद है।

इस साझेदारी का फोकस अतुल ग्रीनटेक के सभी 3-व्हीलर प्लेटफॉर्म पर होगा, जिसमें यात्री वाहनों के लिए अतुल मोबिली और कार्गी वाहनों के लिए अतुल एनर्जी शामिल है। जियो के टेलीमैटिक्स और नेटवर्क कनेक्टिविटी के एकीकरण से ट्रैकिंग, वाहन स्वास्थ्य निगरानी, सुरक्षा और सुरक्षा उपाय और नेविगेशन जैसी सविधाएँ सक्षम होंगी, जिससे ईवी मालिकों को एक सहज अनुभव मिलेगा।



अतल ऑटो के निदेशक डॉ. विजय केडिया ने कहा कि अतुल ग्रीनटेक का लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन को बढ़ाने और ऑटोमोटिव उद्योग में सतत परिवर्तन का समर्थन करने के लिए जिम्मेदारी से भागीदारों का चयन करना है। उन्होंने कहा कि यह सहयोग जियो के डिजिटल इकोसिस्टम का उपयोग करके पर्यावरण और विद्युतीकरण प्रौद्योगिकियों पर अतुल ग्रीनटेक के फोकस को मजबत करेगा।

अंतुल ग्रीनटेक की प्रबंध

निदेशक दिव्या चंद्रा ने जियो के साथ साझेदारी के बारे में आशा व्यक्त की और कहा कि कंपनी को जियो की तकनीक के उपयोग के माध्यम से ग्राहक अनुभव में सुधार करने का भरोसा है। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के

अध्यक्ष आशीष लोढ़ा ने कहा कि अतुल ग्रीनटेक के साथ साझेदारी भारत और उसके बाहर ई-मोबिलिटी परिवर्तन का समर्थन करेगी, साथ ही उन्होंने कहा कि मोबिलिटी प्रौद्योगिकी में संयक्त विशेषज्ञता 3-व्हीलर सेगमेंट में

अनुकूलनशीलता के श्रेष्ठतम उदाहरणों में से एक है। जलवायु परिवर्तन के वर्तमान

परिदृश्य में पशुओं के मध्य आनुवंशिक

जलवायु परिवर्तन का डेयरी उत्पादन पर प्रभाव

पमान आर्द्रता सूचकांक एक



भारतीय मौसम विभाग के अनुसार देश में तापमान वृद्धि की दर वैश्विक के औसत काफी नजदीक है वर्ष 2020 में विगत शताब्दी के वार्षिक तापमान एवं वर्षा के अध्ययनों से यह ज्ञात होता है कि एक ओर जहां वर्ष 1901 से 2019 के मध्य वार्षिक अधिकतम, न्यूनतम एवं मध्यम तापमानों वृद्धि हुई है तो वहीं दूसरी ओर वार्षिक वर्षा में कमी हुई है। वर्ष 1950 से 2015 के मध्य, मानसून वर्षा में 6 की कमी हुई, जिससे मध्य भारत में भारी वर्षा में वृद्धि हुई तथा अकाल एवं सूखे की

घटनाओं में वृद्धि हुई।

व्यापक और सर्वस्वीकृत प्रतिदर्श है। यह केवल तापमान और आर्द्रता के मानों पर ही आधारित होता है तथा यह पशु उत्पादकता को प्रभावित करने वाले अन्य महत्वपूर्ण कारक जैसे ओसांक, वायु वेग एवं सौर विकिरण आदि की उपेक्षा करता है। स्वदेशी नस्ल की गायों की तुलना में, वर्णसंकर गायों तथा भैंसों में उत्पादन एवं प्रजनन क्षमता पर ग्रीष्म तनाव का प्रभाव अधिक परिलक्षित होता है। डेरी पशुओं में ग्रीष्म तनाव के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रभाव दिखाई देते हैं अर्थात समस्थित को बनाए रखने हेतु ऊर्जा उपयोग में वृद्धि के फलस्वरूप पशु उत्पादकता में गिरावट, तथा उपलब्ध चारे में जल विलेय कार्बोहाइड्रेट एवं नाइट्रोजन के संघटन में विचलन के कारण चारे की गुणवत्ता में कमी, दोनों ही पशु उत्पादकता को प्रभावित करती हैं। ग्रीष्म ऋतु में चारा तथा चारा संसाधनों की कमी,

भारतीय मौसम विभाग के अनसार देश में तापमान वृद्धि की दर वैश्विक के औसत काफी नजदीक है। वर्ष 2020 में विगत शताब्दी के वार्षिक तापमान एवं वर्षा के अध्ययनों से यह ज्ञात होता है कि एक ओर जहां वर्ष 1901 से 2019 के मध्य वार्षिक अधिकतम्, न्यूनतम् एवं मध्यम् तापमानों वृद्धि हुई है तो वहीं दूसरी ओर वार्षिक वर्षा में कमी हुई है। वर्ष 1950 से 2015 के मध्य, मानसून वर्षा में 6 की कमी हुई, जिससे मध्य भारत में भारी वर्षा में वृद्धि हुई

चारा फसलों में उच्च लिग्निकरण, शुष्क

एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल की सीमित

उपलब्धता के अतिरिक्त शष्क चारे की

अल्प-पाचकता आदि सभी कारक पश

उत्पादन को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित

तथा अकाल एवं सुखे की घटनाओं में विद्ध हुई। वर्ष 1951 से 2018 के मध्य, चक्रवातों की अपेक्षाकृत कम घटनाओं के बाद भी वर्ष 2000 से 2018 के मध्य, पूर्व तट पर चक्रवातों एवं तफानों में वद्धि हुई ।

पशुओं में उच्च ऊष्मीय तनाव के प्रभावः पशुओं में उच्च ऊष्मीय तनाव के फलस्वरूप दैनिक शारीरिक भार वृद्धि में गिरावट, खाद्य परिवर्तन दक्षता में गिरावट, वृद्धि दर में गिरावट, दुग्ध उत्पादन में गिरावट, प्रजनन क्षमता में गिरावट, मांसपेशीय गुणवत्ता में गिरावट, रोग घटनाओं में वृद्धि, दुग्धकाल अवधि में गिरावट एवं बाँझपन आदि परिलक्षित होते हैं। डेरी पशुओं विशेषकर उच्च उत्पादक डेरी पशुओं में जलवायवीय परिवर्तनों के प्रभाव दुग्ध के उत्पादन एवं संघटन पर परिलक्षित होते हैं। उच्च उत्पादक डेरी पशु अपनी उच्च उपापचय दर के कारण उच्च ऊष्मीय तनाव से अधिक प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त पशु की ख़ुराक में कमी, खाद्य परिवर्तन दक्षता में कमी एवं परिवर्तित कार्यिकीय प्रतिक्रियाएं आदि भी उच्च तापमान- आर्द्रता सूचकांक स्तर के परिणाम स्वरूप परिलक्षित होती हैं। ऊष्मीय तनाव के दौरान, तापमान एवं आर्द्रता में वृद्धि, पशुओं की प्रजनन क्षमता को प्रभावित करती है। गायों में तापमान आर्द्रता सूचकांक 72- 73 और भैंसों में 75 से अधिक होने पर अधिक ऊष्मीय तनाव से गर्भधारण दर में गिरावट आती हैं। इसके अतिरिक्त उच्च ऊष्मीय तनाव के कारण यग्मक जनन एवं यौन व्यवहार में गिरावट, गर्भाशयीय मृत्युदर में वृद्धि गर्भपात में वध्दि एवं जनन अंतराल में विद्ध परिलक्षित होती है। ऊष्मीय तनाव के कारण पशुओं में मदचक्र अवधि में कमी मदकालहीनता एवं शांत मदकाल की घटनाओं में वृद्धि होती है। डेरी पशुओं में



प्रायः उच्च ऊष्मीय तनाव से उत्पन्न उपपचयी, शारीरिक, हार्मोनिक एवं प्रतिरक्षण परिवर्तनों के कारण स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। शारीरिक परिवर्तन के फलस्वरूप, रूमेन आमाशय की गतिशीलता एवं चारा ग्रहण क्षमता में कमी होती है। सम शीतोष्ण जलवायवीय परिस्थितियों में 25-26° सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर चारा ग्रहण क्षमता में गायों एवं भैंसों में क्रमशः 40 व 8-10% की कमी परिलक्षित होती है जबकि बकरियों में 40° सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर चारा ग्रहण क्षमता में 22-35% की कमी होती है। इसके अतिरिक्त उच्च ऊष्मीय तनाव के प्रत्यक्ष प्रभावों में संक्रामक रोगों से ग्रस्त होने की दर में अधिकता एवं प्रतिरक्षा तंत्र की दुर्बलता सम्मिलित है जबिक अप्रत्यक्ष प्रभाव में रोगाणु वाहकों की संख्या में वृद्धि एवं पशुओं की भावी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी तथा प्राणिजन्य रोगों के प्रति अधिक संवेदनशीलता आदि परिलक्षित होते हैं।

ग्रीष्म तनाव के दौरान कृमि संक्रमण, थनैला रोग, खुरपका-मुंहपका रोग तथा बकरियों में प्रायः क्लिनी संक्रमण में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि, विशेषकर झुलसाने वाली गर्मी, नर पशुओं में जलवायवीय तनाव उत्पन्न करती है जो शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता को दीर्घकाल तक प्रभावित करती है। शारीरिक एवं वृषणीय ताप में वृद्धि कोशिकीय उपापचय को परिवर्तित करते हैं जिससे वृषण क्षय में वृद्धि एवं शुक्राणु

की आयु में कमी होती है। ऊष्मीय तनाव को कम करने हेत् रणनीतियांः पशुपलकों एवं किसानों द्वारा प्रायः प्रयोग में जाने वाली रणनीतियों जैसे पशुओं को ताजा चारा और पानी प्रदान करना, सुबह और शाम के अपेक्षाकृत ठंडे घंटों के दौरान पश को भोजन देना एवं दध दोहना, आहार में अतिरिक्त सांद्र मिश्रण प्रदान करना, अतिरिक्त छाया एवं स्नान प्रदान करना तथा पशु के रहने के लिये पर्याप्त स्थान उपलब्ध करवाना आदि

जैव विविधता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। निष्कर्षः जलवायु परिवर्तन के

नकारात्मक प्रभाव वैश्विक स्तर पर एवं भारत में तापमान तथा भारी वर्षा में वृद्धि के रूप में सर्वविदित है। यह परिवर्तन डेरी उद्योग पर सार्थक प्रभाव दर्शाते है। डेरी पशुओं में ऊष्मीय तनाव, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध गुणवत्ता, कोलोस्ट्रम गुणवत्ता, प्रजनन क्षमता, बछड़े के विकास और डेरी पशुओं के समग्र स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जिससे उद्योग में आर्थिक हानि होती है। उच्च दुग्ध उत्पादकता वाले डेरी पशुओं मेंए निम्न दुग्ध उत्पादकता वाले डेरी पशुओं के अपेक्षाकृत दूग्ध उत्पादन और प्रजनन क्षमता में गिरावट अधिक परिलक्षित होती है। भैंस, उचित छाया एवं जलाशय सुविधाओं के साथ गर्म-आद्र वातावरणीय परिस्थितियों में अपेक्षाकृत अधिक संवहनीयता प्रदर्शित करती है। ऊष्मीय तनाव के प्रभावी नियंत्रण की रणनीतियों में पर्यावरण संवर्धन, शीतलन तंत्र, पोषण में परिवर्तन, तनाव-संबंधित पूरक और हार्मीनल उपचार सम्मिलित हैं। एकीकृत फसल-पशुधन प्रणाली एवं ऊष्मा सहिष्णु देशी नस्लों हेतु प्रभावी एवं सक्षम नीतियां बनाने के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का व्यापक अध्ययन महत्वपूर्ण है। पशुधन उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्यावरण मानकों, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और स्थिर पशुधन उत्पादन प्रणालियों को ध्यान में रखते हए उचित

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

रणनीतिक योजना आवश्यक है।

टिप्स और ट्रिक्स: क्रैक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (एफएमजीई)-2025

फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (एफएमजीई) भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने के इच्छुक अंतरराष्ट्रीय मेडिकल स्नातकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। परीक्षा उन उम्मीदवारों की योग्यता और ज्ञान का आकलन करती है जिन्होंने विदेश में अपनी चिकित्सा शिक्षा पूरी की है, जिसका उद्देश्य उनकी योग्यता और विशेषज्ञता का मूल्यांकन करना है। नतीजतन, एफएमजीई परीक्षा को क्रैक करने के लिए पूरी तैयारी, समर्पण और प्रभावी अध्ययन तकनीकों की आवश्यकता होती है। इस चनौतीपूर्ण परीक्षा में सफल होने में आपकी सहायता के लिए, यहां कुछ मूल्यवान युक्तियाँ और युक्तियाँ दी गई हैं 1. पैटर्न और संरचना से स्वयं को परिचित करें एफएमजीई परीक्षा साल में दो बार मई और दिसंबर में होती है। एक छात्र कितने भी प्रयास कर सकता है और उत्तीर्ण होने का मानदंड 50 प्रतिशत अंक है। परीक्षा में 300 प्रश्न होते हैं जो 19 विषयों को कवर करते हुए दो बराबर भागों में विभाजित होते हैं। इसलिए, छात्रों को इस प्रारूप में प्रश्नों का उत्तर देने का अभ्यास करना चाहिए। इसमें ऐसे नोट्स बनाना शामिल हो सकता है जो

इस परीक्षा पैटर्न के अनुकूल हों।2. अपनी बनियादी बातों को कवर करें आदर्श रूप से. छात्रों को अपनी तैयारी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी जैसे प्री और पैरा-क्लिनिकल विषयों से शुरू करनी चाहिए। इससे उन्हें अपनी मूल बातें स्पष्ट करने और सर्जरी और चिकित्सा जैसे अधिक जटिल विषयों की अधिक व्यापक समझ हासिल करने में मदद मिलेगी। पढाई करते समय परीक्षा पैटर्न को याद रखें और महत्वपूर्ण तिथियों, नामों और आंकड़ों पर विशेष ध्यान दें। 3. मुख्य विषयों पर ध्यान दें एफएमजीई परीक्षा की तैयारी करते समय, पिरामिड दुष्टिकोण अपनाना सबसे अच्छा है -इसका मतलब है प्री और पैरा-विषयों (जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है) से शुरू करना और फिर मेडिसिन, सर्जरी और ऑब्रिन जैसे विषयों पर आगे बढना। अंतिम तीन में 19 संवैधानिक विषयों का सबसे बड़ा प्रतिशत (परीक्षा में वेटेज के संदर्भ में) शामिल है। इन विषयों का अध्ययन करते समय, सीवीएस और सीएनएस सिस्टम और उनके संबंधित औषधीय हस्तक्षेप जैसे पहलुओं पर ध्यान दें, सर्जरी में महत्वपूर्ण



ऑपरेशन, टांके और उपकरणों को सीखने और याद रखने के साथ-साथ महत्वपूर्ण स्त्री रोग

संबंधी बीमारियों के विकृति विज्ञान और उपचार, संबंधित जटिलताओं पर भी ध्यान दें।, उपचार,

और प्रसृति के लक्षण । 4. अभ्यास करते रहें एफएमजीई सहित किसी भी परीक्षा को करने के लिए प्रश्नपत्रों को हल करना महत्वपूर्ण है। इससे आपको तय समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रारूप में प्रश्नों का उत्तर देने की आदत हो जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और आपकी तैयारी का एक अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए - इसका सही तरीका यह है कि किसी विषय को समाप्त करें और उससे संबंधित प्रश्नों का प्रयास करने के बाद अपनी धारण शक्ति का परीक्षण करें। इससे बेहतर याददाश्त भी सुनिश्चित होगी और परीक्षा देने में आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा 15. पिछले वर्ष के प्रश्न हल करें पिछले वर्ष के प्रश्नपत्रों को पढ़ना आपकी तैयारी का अभिन्न अंग है। इससे आपको पाठ्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण अनुभागों को समझने में मदद मिलेगी, और यह आपकी तैयारी के लिए एक आवश्यक रोडमैप हो सकता है।6. अपनी तैयारी के लिए सही मंच चुनें पाठ्यक्रम की विशालता, इसे क्रैक करने के लिए की जाने वाली कठोर तैयारी और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केवल 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत छात्र ही परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं. कोचिंग सेंटर जो छात्रों को

ऊष्मीय तनाव प्रबंधन में महत्वपूर्ण

है। सूक्ष्म जलवायवीय संशोधनों में

उपयोग कर, ऊष्मा अपव्यय तंत्र और

पर्यावरणीय शीतलन में सुधार किया जा

सकता है। पोषण प्रबंधन के उपाय, दुग्ध

बढाने हेत ऊष्मा तनाव के दौरान अधिक

पोषक तत्वों से युक्त भोजन के कम मात्रा में

सेवन को संबोधित करता है। आनुवंशिक

संशोधन ऊष्मा सहिष्णु, उच्च उत्पादन

चयन करने पर ध्यान केंद्रित करता है

करने वाली नस्लों की पहचान करने और

जिसमें चमड़ी के रंग और बालों के रंग को

वरीयता देना निहित है। गहरे रंग की चमडी

एवं लंबे बाल वाले गौ वंशीय पशु ऊष्मीय

तनाव के लिए कम अनुकूल होते हैं। हल्के

रंग की चमड़ी एवं छोटे बाल वाली

थारपारकर गाय ऊष्मीय तनाव के प्रति

उत्पादन क्षमता एवं प्रजनन क्षमता को

भूमिका निभाती हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्र-

विशिष्ट प्रजनन रणनीतियों के माध्यम से

ऊष्मा सहिष्णु पशुधन का चयन महत्वपूर्ण

'वाष्पीकरण शीतलन' जैसी प्रणालियों का

प्रभावी ढंग से तैयारी करने में मदद करते हैं, एक वरदान के रूप में उभरे हैं। 7. पुनरीक्षण जरूरी है आपकी तैयारी के अंतिम चरण में चयनात्मक तथापि गहन पुनरीक्षण शामिल होना चाहिए। यह सलाह दी जाती है कि एक साल की पढ़ाई के बाद पहली परीक्षा का प्रयास करें ताकि आपके पास रिवीजन के लिए पर्याप्त समय हो। इसे महत्वपूर्ण आँकड़ों और अवधारणाओं की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिएग्रैंड और मॉक टेस्ट आजमाएं। विभिन्न विषयों को दिए गए वेटेज को ध्यान में रखें और उसके अनुसार समय आवंटित करें 18. निचली पंक्ति बहु मुखी प्रतिभा और परिश्रम एफएमजीई परीक्षा उत्तीर्ण करने का आधार हैं। उचित मार्गदर्शन और विशेषज्ञ सहायता आपके प्रयासों को बढ़ा और उत्प्रेरित कर सकती है और अधिकतम सफलता सुनिश्चित करेगी। इसलिए, सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना और सही तैयारी भागीदारों का चयन करना अभिन्न अंग है। याद रखें, यह एक मैराथन है,

विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकारस्ट्रीटकौरचंदएमएचआरमलोट पंजाब-152107

वरदान या अभिशाप? एनईपी २०२४ की वास्तविकता को डिकोड करना

विजय गर्ग

एनईपी 2024, एनईपी 2020 का उत्तराधिकारी है, जिसका उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली को व्यापक रूप से पुनर्जीवित करना है। यह प्री-स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर कई महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव करता है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं में प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर, ग्रेड 6 से व्यावसायिक शिक्षा की शरूआत, उच्च शिक्षा का पुनर्गठन और बेहतर शिक्षण परिणामों के लिए प्रौद्योगिकी का समावेश शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2024 गहन जांच और बहस का विषय रही है, खासकर भारत में उच्च शिक्षा के लिए इसके निहितार्थ के संबंध में। अधिवक्ता इस क्षेत्र में क्रांति लाने की इसकी क्षमता की सराहना करते हैं, जबकि आलोचक इसकी व्यावहारिकता और दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में आपत्ति व्यक्त करते हैं। एनईपी वैश्विक प्रदर्शन और सहयोग को भी प्रोत्साहित करता है। प्रबंधन संस्थान छात्रों को वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने और अंतरराष्ट्रीय नौकरी बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए विनिमय कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय इंटर्नशिप और विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग की पेशकश कर सकते हैं। इस लेख का उद्देश्य एनईपी 2024 के सुक्ष्म पहलुओं पर गौर करना है, इसके फायदे और नकसान का आकलन करना है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह उच्च शिक्षा के लिए वरदान है या अभिशाप। एनईपी 2024 को समझना एनईपी 2024, एनईपी 2020 का उत्तराधिकारी है, जिसका उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली को व्यापक रूप से पुनर्जीवित करना है। यह प्री-स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर कई महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव करता है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं में प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर, ग्रेड 6 से व्यावसायिक शिक्षा की शुरूआत, उच्च शिक्षा का पुनर्गठन और बेहतर शिक्षण परिणामों के लिए प्रौद्योगिकी का समावेश शामिल है। एनईपी 2024 के वरदान समग्र विकास पर जोरः एनईपी 2024

शिक्षा के लिए बहु-विषयक दृष्टिकोण की वकालत करके समग्र विकास को प्राथमिकता देता है। आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और समस्या-समाधान कौशल का पोषण करके, नीति का लक्ष्य आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को अपनाने में सक्षम पूर्ण व्यक्तियों का निर्माण करना है। पाठ्यक्रम डिजाइन में लचीलापनः एनईपी 2024 के प्रमख सिद्धांतों में से एक पाठयक्रम डिजाइन और कार्यान्वयन में लचीलापन है। यह उच्च शिक्षा संस्थानों को छात्रों और उद्योगों की बढ़ती जरूरतों के अनुरूप अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों को तैयार करने, शिक्षा में नवाचार और प्रासंगिकता को बढ़ावा देने की अनुमति देता है। अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावाः यह नीति उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर ज़ोर देती है। अनुसंधान क्लस्टर, वित्त पोषण के अवसर और उद्योग भागीदारों के साथ सहयोगात्मक पहल स्थापित करके, एनईपी 2024 का लक्ष्य वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति में वैश्विक नेता के रूप में भारत की स्थिति को ऊपर उठाना है। प्रौद्योगिकी का एकीकरणः एनईपी 2024 शिक्षा में प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी क्षमता को पहचानता है और इसके व्यापक एकीकरण की वकालत करता है। सामग्री वितरण, मूल्यांकन और सहयोग के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का लाभ उठाकर, नीति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढाने और शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाटने का प्रयास करती है। 21वीं सदी के लिए प्रासंगिकताः भारत में मौजुदा शिक्षा प्रणाली की अक्सर पुरानी होने और रटने पर केंद्रित होने के कारण आलोचना की जाती है। एनईपी शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला और अंतःविषय बनाने और छात्रों को 21वीं सदी के कार्यबल की मांगों के लिए तैयार करने का प्रयास करती है। समानता और समावेशन के महत्व पर प्रकाश डालनाः शिक्षा में महत्वपूर्ण असमानताएँ हैंभारत के विभिन्न क्षेत्रों, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमियों और जनसांख्यिकीय समूहों में। एनईपी का उद्देश्य यह सनिश्चित करके समानता और समावेशन को बढ़ावा देना है कि सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि

NATIONAL **EDUCATION** POLICY (NEP) 2024



की परवाह किए बिना गुणवत्तापुर्ण शिक्षा तक पहुंच मिले। यह शिक्षा में भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के महत्व पर भी जोर देता है। यह भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और उसका जश्न मनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि शिक्षा सभी छात्रों के लिए सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक है। शिक्षक प्रशिक्षण और विकास पर जोरः शिक्षकों को नई पद्धतियों के साथ संरेखित करने के लिए रणनीतियों में अनुवाद करने के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास और प्रशिक्षण मॉडयल पर बहुत जोर दिया गया है। निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिकाः एनईपी के समावेशी दृष्टिकोण और मिशन को साकार करने के लिए निजी क्षेत्र, विशेषकर उच्च शिक्षा में, की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि 70 प्रतिशत उच्च शिक्षा संस्थान (कॉलेज और विश्वविद्यालय) निजी क्षेत्र द्वारा चलाए जाते हैं। गौरतलब है कि वर्तमान में लगभग 65% प्रतिशत छात्र निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकित हैं। इसके अलावा, निजी क्षेत्र की भागीदारी बहुत आवश्यक वित्तीय संसाधन और नवाचार लाती है। इसलिए, सरकार और नियामक निकायों के लिए व्यावहारिक संस्थागत तंत्र बनाना जरूरी है जो निजी क्षेत्र के योगदान का उपयोग करेगा और उन्हें

एनईपी प्रक्रिया में समान भागीदार के रूप में मान्यता देगा। एनईपी 2024 के संभावित नुकसान कार्यान्वयन चुनौतियाँः जबकि एनईपी 2024 उच्च शिक्षा सुधार के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करता है, इसका सफल कार्यान्वयन महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करता है। बुनियादी ढांचे की सीमाओं से लेकर नौकरशाही बाधाओं तक, नीति निर्देशों को कार्रवाई योग्य सावधानीपूर्वक योजना और निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है, जिसे व्यवहार में हासिल करना मुश्किल हो सकता है। एनईपी 2024 भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार और 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए अपने युवाओं को तैयार करने की दिशा में एक साहसिक कदम का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी सफलता प्रभावी कार्यान्वयन और संभावित चुनौतियों का समाधान करने पर निर्भर करती है। सबसे बड़ी चुनौती कार्यान्वयन बाधाओं को दूर करना, डिजिटल विभाजन को पाटना, मृल्यांकन प्रथाओं की पुनर्कल्पना करना और शिक्षा के व्यावसायीकरण के खिलाफ सुरक्षा करना है। मानकीकृत परीक्षण दुविधाः मूल्यांकन के लिए समग्र दृष्टिकोण की वकालत करने के बावजूद, एनईपी 2024 अकादिमक प्रदर्शन के

लिए एक बेंचमार्क के रूप में मानकीकृत परीक्षण पर निर्भरता बरकरार रखता है। आलोचकों का तर्क है कि यह छात्रों की व्यक्तिगत शक्तियों और सीखने की शैलियों की उपेक्षा करते हुए रटकर याद करने और परीक्षा-केंद्रित सीखने की संस्कृति को कायम रखता है। विशाल कार्यः सबसे पहले, भारत के शिक्षा क्षेत्र का विशाल आकार और विविधता कार्यान्वयन को एक कठिन कार्य बनाती है। उदाहरण के लिए, आइए अकेले स्कूली शिक्षा प्रणाली के आकार पर विचार करें। 15 लाख से अधिक स्कूलों, 25 करोड़ छात्रों और 89 लाख शिक्षकों के साथ, भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली बनी हुई है। उच्च शिक्षा प्रणाली का आकार भी विशाल है। AISHE 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र में लगभग 1,000 विश्वविद्यालयों, 39,931 कॉलेजों और 10,725 स्टैंड-अलोन संस्थानों में 3.74 करोड़ छात्र शामिल हैं। इस प्रकार, इस मेगा शिक्षा नीति का देशव्यापी कार्यान्वयन एक विशाल अभ्यास होने जा रहा है जिसमें राज्य, जिला, उप-जिला और ब्लॉक स्तर पर कई हितधारक शामिल होंगे। नामांकन लक्ष्य हासिल करने में चुनौतीः चुंकि नीति का लक्ष्य 2035 तक सकल नामांकन अनुपात को दोगुना करना है, इसके लिए हर महीने

एक नए विश्वविद्यालय के निर्माण की आवश्यकता होती है।अगले 15 वर्षों के लिए k, जो एक बड़ी चुनौती है। शिक्षकों की उपलब्धता और प्रशिक्षण का अभावः उन्नत पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से वितरित करने के लिए, भारत को सक्षम शिक्षकों के एक बड़े समूह की आवश्यकता है जो नए शैक्षणिक दृष्टिकोण से परिचित हों। चूंकि शिक्षक आम तौर पर एक अनुशासनात्मक एंकरिंग संस्कृति साझा करते हैं, इसलिए असाधारण कौशल वाले ऐसे शिक्षकों का होना मुश्किल है जो एक क्षेत्र में विशेषज्ञ हों और साथ ही अन्य विषयों में भी रुचि रखते हों। अपर्याप्त फंडिंगः प्रमुख पहलों के सफल क्रियान्वयन के लिए दशकों तक पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की आवश्यकता होती है। इस संबंध में एनईपी में कहा गया है कि नई नीति के लक्ष्यों को साकार करने के लिए देश को शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत तक बढ़ाना होगा। एकाधिक प्रवेश और निकासः एनईपी में बड़ी छात्र आबादी के कारण भारत में एकाधिक प्रवेश और निकास विकल्पों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे उच्च शिक्षा में उच्च वार्षिक प्रवेश प्राप्त हो सकता है। विश्वविद्यालयों के लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल हो सकता है कि कितने छात्र इसमें शामिल होंगे और बाहर निकलेंगे और सरकार को हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने और प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और डिग्री जैसे विभिन्न स्तर के कार्यक्रमों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है।शिक्षा के प्रति समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, समावेशिता और पहुंच को बढ़ावा देकर, और उन्नत सीखने के अनुभवों के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, एनईपी 2024 में भारत में शिक्षा के भविष्य को आकार देने में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनने की क्षमता है। हालाँकि, इसके संभावित नुकसानों पर सावधानीपूर्वक विचार करना और उन्हें कम करने के लिए सक्रिय उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि यह वास्तव में एक उज्जवल, अधिक न्यायसंगत शैक्षिक परिदृश्य के अपने वादे को पूरा करता है।

आलू, प्याज, टमाटर बिगाड़ रहे रसोई का हिसाब, कब मिलेगी महंगाई से राहत?

जुलाई-अगस्त में थोड़ा सुस्त रहने के बाद खुदरा महंगाई फिर से आसमान पर पहुंच गई है। सितंबर 2024 में खुदरा महंगाई 5.49 प्रतिशत दर्ज की गई जो अगस्त में महंगाई दर 3 .14 प्रतिशत थी। सब्जी के खुदरा दाम में 36 प्रतिशत का इजाफा हुआ। अगर महंगाई इसी हिसाब से बढ़ती रही तो आरबीआई दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती से परहेज कर सकता है।

नई दिल्ली। आलू, प्याज, टमाटर के साथ हरी सब्जियों की बढ़ी हुई कीमतों ने सितंबर माह की ख़ुदरा महंगाई दर को नौ माह के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर की खुदरा महंगाई दर 5.49 प्रतिशत दर्ज की गई जबकि इस साल अगस्त की महंगाई दर 3.14 प्रतिशत थी। सितंबर में सब्जी-फल के साथ दाल की कीमतों से भी खुदरा महंगाई दर को समर्थन मिला।

पिछले डेढ़ माह से आलू, प्याज की कीमत 50-70 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच चल रही है तो टमाटर के खुदरा भाव पिछले महीने 60-80 रुपए प्रति किलोग्राम थे जो फिलहाल 100 रुपये किलोग्राम के पार जा चुके हैं।

सितंबर में विभिन्न वस्तुओं की खुदरा महंगाईदर

वस्तु महंगाई दर (प्रतिशत में) अनाज 6.84

मांस-मछली 2.66 खाद्य तेल-घी

चीनी 3.46



कपड़े व फुटवियर 2.71 यातायात व संचार 2.77 तैयार भोजन व मिठाई क्या ब्याज दरों में नहीं होगी कटौती?

www.newsparivahan.com

आल. प्याज और टमाटर के दाम कम नहीं होने से अक्टूबर की खुदरा महंगाई दर भी सितंबर की तरह पांच प्रतिशत के पार रह सकती है। इसका नतीजा यह होगा कि आगामी दिसंबर में भी आरबीआई ब्याज दरों में कटौती करने की स्थित में नहीं होगा। पिछले कई महीनों से महंगाई दर के

पांच प्रतिशत से नीचे रहने की वजह से गत सप्ताह आरबीआई ने दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती करने के संकेत दिए थे।

सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 9.4 प्रतिशत हो गई जबिक इस साल अगस्त में यह दर 5.66 प्रतिशत थी। सितंबर में आलू, प्याज टमाटर वगैरह मिलाकर कुल सब्जी की खुदरा महंगाई दर में पिछले साल सितंबर की तलना में 36 प्रतिशत की बढोतरी दर्ज की गई। दाल के दाम में 10 प्रतिशत तो फल में 7.65 प्रतिशत का इजाफा रहा । सितंबर

में मसाले के खदरा दाम में 1 39 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

कम विकसित राज्यों में अधिक महंगाई सरकारी आंकडों के मृताबिक कम विकसित राज्यों में राष्ट्रीय औसत से अधिक खुदरा महंगाई दर है।बिहार में सबसे अधिक खुदरा महंगाई दर 7.5 प्रतिशत रही जबकि दिल्ली में खुदरा महंगाई दर 3.67 प्रतिशत रही।सितंबर में उत्तर प्रदेश में खुदरा महंगाई दर 6.74 प्रतिशत, छत्तीसगढ में 7.36 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 6.20 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 5.94 प्रतिशत, उड़ीसा में 6.56 प्रतिशत रही।

क्या 'सबसे बड़े IPO' में करना चाहिए निवेश? भारी नुकसान करा चुके हैं DLF, रिलायंस पावर और पेटीएम

हंडई के आईपीओ को देश का सबसे बडा आईपीओ कहकर प्रचारित किया जा रहा है। हुंडई फिलहाल दुनिया के तीसरी सबसे बड़े कार बाजार भारत की दूसरी सबसे बडी कंपनी है। इसने अगले कुछ साल के दौरान भारत में 32000 करोड़ के निवेश का प्लान भी बनाया है। लेकिन डीएलएफ लिमिटेड रिलायंस पावर पेटीएम जैसे सबसे बडे आईपीओ के रिटर्न का रिकॉर्ड काफी खराब है।

नई दिल्ली। पिछले कुछ समय से निवेशकों के बीच हर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) में पैसे लगाने का चलन बन गया। कई लोग लिस्टिंग गेन के चक्कर में फंडामेंटल तक एकदम दरिकनार कर देते हैं। लेकिन, आईपीओ के आकार के हिसाब से निवेश करने पर आपको घाटा उठाना पड़ सकता है। यह बात आम निवेशकों को निश्चित तौर पर समझने की जरूरत है। मंगलवार को देश की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी हंडई मोटर इंडिया पहली बार शेयर बाजार में उतरने जा रही है और बाजार में एक बार फिर से सबसे बड़े आईपीओ का ढोल पीटा जा रहा है। हुंडई

का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 15

अक्टूबर को खुलेगा। इस आईपीओ का साइज

27,870 करोड़ रुपये का हो सकता है।

बेशक हंडई फिलहाल दिनया के तीसरी सबसे बडे कार बाजार भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। भारत को लेकर इसका प्लान भी लंबी अवधि का है। फिर भी यह बात याद रखनी चाहिए कि अतीत में डीएलएफ लिमिटेड, रिलायंस पावर, पेटीएम जैसी कंपनियों ने अपने-अपने आईपीओ की देश के सबसे बड़े आईपीओ के तौर पर मार्केटिंग की, लेकिन इनमें पैसे लगाने वाले निवेशकों को नुकसान ही हुआ।

डीएलएफ से निवेशकों को मिली मायुसी रियल एस्टेट सेक्टर की मशहर कंपनी डीएलएफ ने साल 2007 में अपने आईपीओ की सबसे बडे इश्य के तौर पर ब्रांडिंग की। इसके आईपीओ का आकार 9,187 करोड़ रुपये था। यह इश्यू तकरीबन साढ़े तीन गुणा ओवरसब्सक्राइब हुआ था, लेकिन खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित शेयरों के प्रति खास उत्साह नहीं दिखा था।

आईपीओ का मुल्य 525 रुपये प्रति शेयर तय किया गया। तकरीबन पांच वर्ष बाद कंपनी ने 600 रुपये प्रति शेयर की दर से बायबैक का फैसला किया। डीएलएफ ने साल 2008 में करीब 1200 रुपये का अपना ऑलटाइम हाई बनाया। लेकिन, 16 साल बीतने के बावजूद दोबारा कभी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाई। फिलहाल डीएलएफ के शेयर 850 रुपये के आसपास कारोबार कर रहे हैं।

गरीब देशों के लिए बड़ा संकट बन रहा कर्ज का जाल, प्राकृतिक आपदाओं की मार भी बढ़ी

परिवहन विशेष न्यूज

दुनिया के 26 सबसे गरीब देशों की मुसीबतों लगातार बढ़ रही हैं। ये देश कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। इन 26 गरीब देशों की अर्थव्यवस्था आज भी कोरोना महामारी के ठीक पहले की तुलना ज्यादा कमजोर है जबिक बाकी दुनिया काफी हद तक कोविड के झटके से उबर चुकी है। आइए जानते हैं कि इन गरीब देशों की सबसे मुश्किल वजह।

नई दिल्ली। दुनियाभर में गरीब देश लगातार खस्ताहाल होते जा रहे हैं। एक तो वहां गरीबी बढ़ रही है, दूसरे कर्ज का जाल भी कसता जा रहा है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के 26 सबसे

गरीब मुल्क इस वक्त भारी कर्ज में डूबे हुए हैं, जो साल 2006 के बाद सबसे अधिक है।

इन 26 देशों में दुनिया के 40 फीसदी सबसे अधिक गरीब रहते हैं। ये लोग न सिर्फ गरीबी और कर्ज के जाल में फंसे हैं, बल्कि यहां कुदरती आफतों और दूसरी मुसीबतों का खतरा सबसे अधिक रहता है।

क्या कहती है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट

वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि इन 26 गरीब देशों की अर्थव्यवस्था आज भी कोरोना महामारी के ठीक पहले की तुलना ज्यादा कमजोर है। वहीं, बाकी दुनिया काफी हद तक कोविड के झटके से उबर चुकी है। उनकी तरक्की की रफ्तार कमोबेश पहले की तरह हो गई है।

यह रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की सालाना मीटिंग शुरू होने से ठीक पहले जारी हुई है। इससे जाहिर होता है कि



अत्यधिक गरीबी उन्मुलन की कोशिशों को

सबसे गरीब देशों- इंटरनेशनल डेवलपमेंट

वित्तपोषण कोष को दोबारा भरने के लिए

कितनी है पर कैपिटा इनकम इन 26 सबसे गरीब देशों में

सालाना प्रति व्यक्ति आय (Annual Per-Capita Incomes) 1,145 डॉलर से भी कम है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि ये देश IDA से मिलने वाले ग्रांट और तकरीबन शुन्य के करीब वाले ब्याज दर पर निर्भरता काफी ज्यादा बढ़ गई

है, क्योंकि मार्केट फाइनेंसिंग

तकरीबन खत्म हो चुकी है। इन देशों को डेट-टु-जीडीपी रेशियो 72 फीसदी है, जो 18 साल के उच्चतम स्तर पर है। इस ग्रुप के आधा देश या तो कर्ज संकट में फंस चुके हैं, या फिर फंसने की कगार पर हैं। मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती। 26 में से करीब दो तिहाई देश या तो सशस्त्र संघर्ष में उलझे हए हैं या फिर संस्थागत और सामाजिक चुनौतियों

के चलते शासन व्यवस्था बनाए रखने में मुश्किल हो रही है। इससे विदेशी निवेश से

लेकर निर्यात तक सभी चीजों पर बुरा असर पड़ रहा है। इससे इन देशों में महंगाई और मंदी का खतरा लगातार बढ़ रहा है।

क्या है इंटरनेशनल डेवलपमेंट IDA गरीब देशों में जरूरी सुविधाएं

उपलब्ध कराती है। इसे अमुमन हर तीन साल में विश्व बैंक के शेयरधारक देशों के योगदान से फिर से भरा जाता है। इसने 2021 में रिकॉर्ड 93 अरब डॉलर जुटाए। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा इसे 6 दिसंबर तक 100 अरब डॉलर के पार ले जाने का प्रयास कर रहे हैं।

पिछले दशक में प्राकृतिक आपदाओं ने भी इन गरीब देशों पर काफी अधिक प्रभाव डाला है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि 2011 और 2023 के बीच प्राकृतिक आपदाओं से सकल घरेलु उत्पाद का औसत वार्षिक नुकसान २ फीसदी था। यह निम्न-मध्यम आय वाले देशों के औसत से पांच गुना अधिक है। इससे इन देशों में जरूरी स्विधाओं के लिए काफी अधिक निवेश की जरूरत का पता चलता है।

क्या है UPI लाइट, RBI ने क्यों बढ़ाई इसकी लिमिट; किसे मिलेगा फायदा?

यूपीआई लाइट यूजर को सीधे अपने डिवाइस पर पैसे स्टोर करने की अनुमति देता है जैसे कि आप जेब में पैसे लेकर घूमते हैं। यूपीआई लाइट वॉलेट में यूजर अब 5000 रुपये तक का बैलेंस रख सकते हैं। यह सीमा पहले सिर्फ 2000 रुपये थी। आरबीआई ने यूपीआई123पे पर पेमेंट लिमिट बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दी है जो पहले सिर्फ 5 हजार रुपये थी।

नई दिल्ली।रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल पेमेंट सॉल्युशंस UPI लाइट की लिमिट बढ़ा दी है। अब इसे इस्तेमाल करना अधिक सविधाजनक हो गया है। आइए जानते हैं कि यूपीआई लाइट क्या है, इसकी लिमिट कितनी बढ़ी है और लिमिट बढ़ने से

क्या है यूपी आई लाइट (UPI Lite)?

यपीआई लाइट UPI ऐप में एक ऑनलाइन वॉलेट है। इसे भारतीय राष्ट्रीय भगतान निगम (NPCI) नेपिन एंटर किए बिना पेमेंट करने की सुविधा के साथ पेश किया है। यपीआई लाइट पेमेंट सिस्टम असल में बैंकिंग इन्फ्रास्टक्चर का इस्तेमाल किए बगैर काम करता है। इसका इस्तेमाल अधिकतर लोग छोटी रकम की खरीदारी के लिए करते हैं। जैसे कि दुध, फल या फिर सब्जियां।

यूपीआईलाइट कैसे काम करता है

. यपीआई लाइट यजर को सीधे अपने डिवाइस पर पैसे स्टोर करने की अनमति देता है, जैसे कि आप जेब में पैसे लेकर घूमते हैं। इससे पेमेंट काफी आसान हो जाता है। साथ ही, हर ट्रांजैक्शन के लिए बैंक सर्वर तक पहुंचने की जरूरत नहीं रहती। इससे फीचर फोन यूजर को भी डिजिटल भुगतान सहूलियत मिलती है। साथ ही, यूपीआई लाइट वॉलेट यूज करने वालों के छोटी रकम का ट्रांजैक्शन सरल हो जाता है।

थोक महंगाई में उछाल, सिन्जियों के आसमान छूते भाव का दिखा असर

खाने-पीने की चीजों की कीमतों में उछाल के बीच थोक महगाई सितंबर में सालाना आधार पर 1.84 प्रतिशत हो गई। इससे एक महीना पहले यानी अगस्त में यह 1.31 प्रतिशत थी। हालांकि यह फिर भी अनुमान से कम रही। एक्सपर्ट का मानना था कि इस बार थोक महंगाई 1.92 फीसदी तक पहुंच सकती है। खुदरा महंगाई के आंकर्ड़े भी आज ही जारी होंगे।

नर्इ दिल्ली। आम जनता को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। सोमवार को जारी डेटा के मताबिक, सितंबर में होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) 1.84 फीसदी हो गई। यह अगस्त में 1.31 फीसदी थी। पिछले साल की बात करें, तो (-)0.07 फीसदी थी। खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति पिछले महीने बढकर 11.53 प्रतिशत हो गई। अगस्त में यह 3.11 प्रतिशत थी। हालांकि,



सितंबर में थोक महंगाई फिर भी एक्सपर्ट के अनुमान से कम रही। एक्सपर्ट का मानना था कि सितंबर में थोक महंगाई 1.92 फीसदी रह सकती है।

क्यों बढ़ रही थोक महंगाई

थोक महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है. सब्जियों के आसमान छूते दाम। आलू और प्याज की मद्रास्फीति सितंबर में क्रमशः 78.13 प्रतिशत और 78.82 प्रतिशत पर

उच्च स्तर पर बनी रही।ईंधन और बिजली

प्रतिशत की अपस्फीति थी।

सरकार ने क्या कहा?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा. ₹सितंबर 2024 में मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों, खाद्य उत्पादों, अन्य विनिर्माण, मोटर वाहनों, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों के निर्माण, मशीनरी और उपकरणों के निर्माण आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण है।₹

रिजर्व बैंक (RBI) मौद्रिक नीति तैयार करते समय मख्य रूप से खुदरा मुद्रास्फीति को ध्यान में रखता है। उसने इस महीने की शुरुआत में अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में बेंचमार्क ब्याज दर या रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर जस का तस रखा। खुदरा मद्रास्फीति के आंकडे भी आज ही आएंगे।

दो तरह की महंगाई दर भारत में इन्फ्लेशन दो तरीके होती है. एक रिटेल और होलसेल इन्फ्लेशन।रिटेल

यानी खुदरा महंगाई दर उन कीमतों के हैं। जैसे कि आप सब्जी या कोई चीज खरीदी। इसे कंज्यमर प्राइस इंडेक्स (CPI) भी कहते हैं। वहीं, होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) थोक बाजार में कारोबारियों के बीच आपस में लेन-देन वाली कीमतों से तय होता है।

कैसे तय होती है महंगाई दर? महंगाई मापने के लिए अलग-अलग आइटम को शामिल किया जाता है। उनका वेटेज भी अलग-अलग होता है। थोक महंगाई में मैन्यफैक्चर्ड प्रोडक्टस की हिस्सेदारी 63.75 फीसदी, प्राइमरी आर्टिकल जैसे फूड 22.62 फीसदी और फ्यूल एंड पावर 13.15 फीसदी होती है। वहीं, रिटेल महंगाई में फूड और प्रोडक्ट की भागीदारी 45.86 फीसदी और हाउसिंग की 10.07 फीसदी होती है। इसमें फ्यूल समेत अन्य आइटम्स की भी भागीदारी होती

सामान्य और तत्काल टिकट की बुकिंग मिस हो जाए, तो अपनाएं ये रामबाण तरीका

इस त्योहारी सीजन में दिवाली और छठ जैसे खास मौकों पर हर कोई घर जाना चाहता है। लेकिन कई बार भारी भीड के चलते रेलवे टिकट बुक (Tatkal Train Booking) करने में मुश्किल होती है। सामान्य और तत्काल टिकट बुक करने में निराशा हाथ लगती है। ऐसे में आप करेंट टिकट की बुकिंग आजमा सकते हैं। आइए इसे बुक करने के प्रोसेस को वस्तार से

नईदिल्ली।भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (ITCTC) रेल यात्रियों को कई शानदार सुविधाएं देता है। इससे आप रेलवे टिकट की बुकिंग से लेकर यात्रा के दौरान खाने-पीने की चीजें ऑर्डर कर सकते हैं।

लेकिन, ITCTC की कुछ सुविधाएं ऐसी हैं, जिनके बारे में अधिक लोग नहीं जानते। जैसे कि करेंट टिकट (Current ticket)। इस सुविधा के तहत आप यात्रा वाले दिन भी रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन, इसके लिए कुछ चीजों का ध्यान रखने की जरूरत होती है।

करेंट टिकट की जरूरत क्यों रेलवे अमुमन ट्रेन चलने की तारीख से तीन



महीने पहले ट्रेन टिकट बुकिंग खोलता है। वहीं, तत्काल कोटा टिकट की बुकिंग ट्रेन के निर्धारित सफर से एक दिन पहले खलती है। सामान्य टिकट की बुकिंग शुरुआत में ही करने पर सीट

मिल जाती है। वहीं, तत्काल टिकट में टिकटों की संख्या काफी सीमित होती है। ऐसे में बुकिंग कन्फर्म होने की गंजाइश काफी कम रहती है। अगर आपने सामान्य और तत्काल, दोनों

टिकट सिस्टम आजमा सकते हैं। क्या होता है करेंट टिकट आपने IRCTC के प्लेटफॉर्म से सामान्य,



वेटिंग या फिर तत्काल टिकट बुक किया होगा। ये सभी टिकट चार्ट तैयार होने से पहले बुक किए जाते हैं। लेकिन, करेंट टिकट को आप चार्ट तैयार होने के बाद IRCTC की वेबसाइट या ऐप से बुक कर सकते हैं। इसमें चार्ट बनने के बाद जो सीटें खाली बच जाती हैं, उनकी बुकिंग होती है।

करेंट टिकट कैसे बुक करें करेंट टिकट को यात्रा के दिन ही बुक किया जाता है, तो कुछ खास चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आप करेंट टिकट को इस प्रोसेस के जरिए

बुक कर सकते हैं। IRCTC ऐप में 'ट्रेन' बटन पर क्लिक करें और अपना डेस्टिनेशन और सोर्स स्टेशन टाइप

जाने की (Departure) की तारीख उसी दिन की होनी चाहिए, जिस दिन आप टिकट बुक

सोर्स, डेस्टिनेशन और डिपार्चर डेट चुनने के बाद 'ट्रेन सर्च' बटन पर क्लिक करें।

अब आपको स्क्री पर उस रूट पर सभी उपलब्ध ट्रेनों की सूची दिखाई देगी। अपनी पसंद की कैटेगरी के टिकट पर क्लिक

करें- जैसे कि CC, EC, 3AC, 3E, इत्यादि। अगर उस ट्रेन के लिए कोई करेंट टिकट उपलब्ध है, तो यह 'CURR_AVBL-' के रूप

इस सविधा में कम व्यस्त रूट पर करेंट टिकट मिलने की संभावना अधिक होती है।

संस्कारशालाः पैसा - पुण्य और पाप का खेल - सही कर्मों से कमाएं असली दौलत

अंक

आज के दौर में पैसा जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। हर कोई अधिक से अधिक कमाने की दौड़ में लगा हुआ है। चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो या किसी भी प्रकार की सेवा, हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम जितना हो सके, उतना अधिक पैसा कमाएं। लेकिन इस अंधी दौड़ में कहीं न कहीं हम यह भूल जाते हैं कि असली दौलत केवल पैसा नहीं, बल्कि पुण्य और अच्छे कर्म होते हैं, जो हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बनाते हैं। कहते हैं कि "पैसा जरूरी है, लेकिन हर चीज का

कहते हैं कि "पैसा जरूरी है, लेकिन हर चीज का अपना दायरा होता है।" पैसा हमें जीवन की सुविधाएं दे सकता है, लेकिन सच्ची खुशी और आत्मसंतुष्टि तभी मिलती है जब हम अच्छे कर्म करते हैं। आज के समय में पुण्य कमाना एक पुरानी बात लगती है, लेकिन असल में यही हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है और हमें सच्ची समृद्धि प्रदान करता है।

यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं, जिनके माध्यम से हम पुण्य कमाकर अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और बुरे कर्मों से मुक्त हो सकते हैं:

1.दया और करुणा का अभ्यास करें सच्चे पुण्य का सबसे बड़ा आधार है दूसरों के प्रति

जीव कुमार ने संजीत कुमार से पैसे वापस मांगे। जिस पर वकील ने पैसे न होने के एवज में 54 चेक काट कर दे दिए। साथ ही, अपनी गाड़ी भी पैसे के बदले दे दी और एक एग्रीमेंट बनाया। यह सारी घटना 2 अक्टूबर को हुई। उसके बाद 3 तारीख को वकील संजीत कुमार पंडरा थाने पहुंचे और उन्होंने संजीव कुमार और अन्य लोगों पर अपहरण और मारपीट का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। उधर रांची के सीईओ का नाम हटाने में 7करोड रुपए वसूले जाने की भी खबर है। जिसका एक प्रार्थमिकी संजीव कुमार द्वारा दर्ज कराई गई है। मामला ईडी से जूडे होने एवं हाई लेवल होने के कारण पुलिस जांच में जुट गई है पर मिडिया को कुछ कहने से बच रही है। वैसे ईडी स्वयं जांच एजेन्सी है जिसे राज्यों रोकने हेतु कुछ राज्यों के सरकारें आवश्यक कदम उठाये थे पर उसकी जांच में धन की उगाही कैसे होती है देखना बड़ा दिलचस्प होगा।

हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में किसकी बनेगी सरकार? आज आएगा जनता का फैसला

हरियाणा और जम्मू – कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम आज आएंगे। इन प्रदेशों में किसकी सरकार होगी... यह तस्वीर दोपहर तक साफ होने की उम्मीद है। हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर हैं। पिछले 10 वर्षों से प्रदेश की सत्ता पर भाजपा ही काबिज है। जम्मू और कश्मीर में लोगों का छह साल बाद सरकार का इंतजार खत्म होगा।

नई दिल्ली। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन मुख्यमंत्री का ताज पहनेगा इससे जुड़े सभी सवालों पर से मंगलवार को परदा हट जाएगा। दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे मंगलवार को घोषित हो जाएंगे। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर के लोगों का पिछले छह सालों से सरकार को लेकर चला रहा इंतजार खत्म हो जाएगा। जम्मू-कश्मीर में इससे पहले विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे। इसके बाद वहां पीडीपी और भाजपा गठबंधन की सरकार बनी थी, हालांकि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पायी थी और

दया और करुणा। हमें हर व्यक्ति और जीव के प्रति संवेदनशील और सहानुभूतिशील होना चाहिए। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, तो हम पुण्य कमाते हैं। यह न केवल दूसरों की मदद करता है बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है।

2.ईमानदारी और नैतिकता का पालन करें

www.newsparivahan.com

जीवन में पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह तभी सच्चा होता है जब हम उसे ईमानदारी और नैतिकता के साथ कमाएं। गलत तरीकों से कमाया गया पैसा न केवल हमें बुरे कर्मों में धकेलता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी कलुषित करता है। ईमानदार और नैतिक रूप से पैसा कमाने से पुण्य के साथ-साथ आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त होती है।

3.दान और परोपकार करें

पैसा तब तक सार्थक नहीं होता जब तक हम उसका सही उपयोग न करें। जरूरतमंदों की सहायता करना, गरीबों को भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, यह सब पुण्य के कार्य हैं। जब हम अपने धन का एक हिस्सा समाज के भले के लिए खर्च करते हैं, तो यह सीधे हमारे अच्छे कर्मों को बढ़ाता है।

4. अहंकार से दूर रहें



अक्सर जब व्यक्ति के पास अधिक पैसा हो जाता है, तो उसके अंदर अहंकार आने लगता है। लेकिन यह हमें पुण्य की राह से भटका देता है। अहंकार से बचने के लिए हमें हमेशा विनम्न रहना चाहिए और अपने संसाधनों को दूसरों के साथ बांटने की भावना विकसित करनी चाहिए। विनम्नता और सेवा का भाव हमें पुण्य की दिशा में आगे बढ़ाता है। 5. पर्यावरण की रक्षा करें आज के समय में पर्यावरण की देखभाल भी एक बड़ा पुण्य का कार्य है। प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी को समझना और उसके संरक्षण के लिए काम करना हमारे अच्छे कर्मों को बढ़ाता है। पौधे लगाना, जल को संरक्षित करना और पर्यावरण व स्वच्छ रखना हमारे पुण्य कार्यों का हिस्सा बन

६ चानकाणमारको

हम जो जानते हैं, वह दूसरों के साथ बांटने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। शिक्षा और ज्ञान का प्रसार एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य है, जो न केवल समाज को सशक्त बनाता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है। दूसरों को सिखाने और मार्गदर्शन करने से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं।

7.समयका सदुपयोगकरें

हमारे जीवन का हर पल अनमोल है। इसे सही दिशा में लगाना और अपना समय अच्छे कार्यों में बिताना हमें पुण्य प्रदान करता है। बुराई और नकारात्मकता से दूर रहकर जब हम सकारात्मकता और सेवा के कार्यों में समय बिताते हैं, तो यह हमारे जीवन को पुण्य से भर देता है।

बुज्य स नर दत्ता है। 8. क्षमा और सहनशीलता का अभ्यास करें किसी के प्रति घृणा या द्वेष रखना हमारे कर्मों को खराब करता है। हमें दूसरों को माफ करना सीखना चाहिए और सहनशीलता का अभ्यास करना चाहिए। क्षमा और सहनशीलता हमारे कर्मों को शुद्ध करते हैं और हमें पुण्य की ओर ले जाते हैं। 9.स्वास्थ्यऔरस्वच्छताकाख्यालरख

स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखना भी पुण्य का कार्य है। अपने शरीर को स्वस्थ और स्वच्छ रखना, और दूसरों को भी इसका महत्व समझाना, यह भी पुण्य की राह पर एक कदम है। जब हम स्वच्छता और स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, तो हम समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं।

10. सद्भावना और सकारात्मक सोच बनाए

सकारात्मक सोच और सद्भावना हमें जीवन में ऊँचाई तक ले जाती है। दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखना, और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना हमारे पुण्य कार्यों को बढ़ाता है। पैसा जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन सच्चा सुख और समृद्धि पुण्य कमाने में है। अच्छे कर्म और इंसानियत दिखाने से हमें जीवन में आत्मिक संतुष्टि और शांति मिलती है। जितना अधिक हम पुण्य के कार्य करेंगे, उतना ही हमारा कर्म सुधार होगा और बुरे कर्मों से मुक्ति मिलेगी। असली दौलत धन से नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कर्मों से मिलती है। इंसानियत के रास्ते पर चलते हुए ही हम पुण्य कमा सकते हैं और जीवन को सही मायनों में सार्थक बना सकते हैं।

ऑनलाइन मार्केटप्लेस और डिलीवरी के जरिए भी पटाखों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लागू रहेगा

सुषमा रानी

नर्इदिल्ली। 'आप'' सरकार ठंड के मौसम के दौरान दिल्ली में वाय प्रदुषण को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी के मद्देनजर सरकार ने दिल्ली के अंदर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर व्यापक प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। यह प्रतिबंध तुरंत प्रभावी होगा और 1 जनवरी, 2025 तक सारे प्रतिबंध लागू रहेंगे। वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत दिल्ली प्रदुषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा। वायु प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई में सरकार यह एक अहम प्रयास है।

दरअसल, ठंड के मौसम के दौरान अक्सर हवा की गुणवत्ता में गिरावट देखी जाती है। इसी के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया है। क्योंकि पटाखों के उपयोग से हवा की गुणवत्ता और भी खराब होने की संभावना होती है। खासकर



सर्दियों के महीनों में पड़ने वाले त्योहारों के दौरान प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ जाता है। पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध वायु प्रदूषण को कम करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सरकार की व्यापक पहल का हिस्सा

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सर्वविदित है कि पटाखों के इस्तेमाल से हवा की गुणवत्ता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। पटाखों के प्रतिबंध के निर्णय के पीछे हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली की हवा सांस लेने योग्य बनी रहे। यह प्रतिबंध ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से पटाखों की बिक्री पर भी सख्ती से लागू होगा।

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में सर्दियों में दिल्ली को अत्यधिक प्रदूषण का सामना करना पड़ा है। लिहाजा, सरकार का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए। सरकार दिल्ली की जनता से प्रदूषण के खिलाफ इस सामूहिक लड़ाई में सहयोग और समर्थन की अपील करती है।

वहीं, दिल्ली पुलिस को पटाखों के पूर्ण प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस को प्रतिदिन इसकी रिपोर्ट डीपीसीसी को सौंपनी होगी। यह पहल दिल्ली में वायु गुणवत्ता को सुधारने की दीर्घकालिक अवधि रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है।

road to paralympics

ग़ज़ल : ज़िन्दगी की ज़रूरत हर हाल में मरने से पहले जीने की जंग है, मुसीबतों से हर हाल पार पाने की उमंग है।

ये जिंदगी मुस्कुराते हुए बिताने का प्रसंग है दायरा है बेहिसाब इस फ़लक का नवरंग हैं।

इन चाँद-तारों से परे जाने की जिन्हें तलब है, उन्हें ही दो यह आसमां इसमें क्या गलत है ?

कभी तो बढ़ा लिया करो प्यार से दो कदम। उन्हें अपना बनाने की तुम्हें ही तो जरुरत है,

अपनी नाराजगी लिए न बैठा करों हरदम.

खुशियाँ ही खुशियाँ हैं फिर क्यों नफरत है ? हटाओं ये उदासियों के बादल बनाओ रिश्ते.

देखों आसपास ही तुम्हें मिल जाएंगे फरिश्ते।

ये एक ही घर में तो हैं निवास क्या मुहूरत हैं, खाली मकानों को घर बनाने की जरुरत है।

> संजय एम. तराणेकर (कवि, लेखक व समीक्षक) इंदौर (मध्यप्रदेश) 98१६०-१५९८६

महापूजा अर्चना की और सिंदुर खेला (कवि व समीक्षक संजय एम तराणेकर की क़लम से)

इन्दौर। चिडियाघर स्थित बंगाली क्लब में बंगाली समाज द्वारा पांच दिवसीय दुर्गा पजा उत्सव के अंतिम दिन महिलाओं द्वारा सिंदुर खेला का आयोजन कर मां की महापूजा अर्चना की और धुनुजी नृत्य किया गया । बंगाली समाज में माताजी की स्थापना और पूजाअर्चना और सिंदूर खेला महिलाओं द्वारा खेला जाता है। ये सिंदूर खेलना बंगाली समाज की परम्परा है। धुनुची नृत्य को देखने के लिए पूरा बंगाली समाज उमडा । देवी दुर्गा माँ के दरबार में महिला और पुरुषों ने हाथ में जलता हुआ दीया लेकर अदभुत धुनुची नृत्य किया। बंगाली स्कूल एंड क्लब के वॉइस प्रेसीडेंट रवि शंकर रॉय चौधरी और को – सेक्रेटरी अंबुज दत्ता ने बताया कि शुरुआत बिहित पूजा से हुई। उसके बाद बलिदान, कुमारी पूजा और पुष्पांजलि हुई। दोपहर में देवी माँ को खीर के प्रसाद का भोग लगाया और सबने भोग ग्रहण किया। शाम को आरती हुई और रात्रि को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

शिडी साई बाबा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है: भारत के पैरालंपिक चैंपियनों की जीत का जश्न

सुषमा रानी

नई दिल्ली, शिर्डी साईं बाबा फाउंडेशन, जो पैराथलीट्स का आध्यात्मिक मार्गदर्शन और उनकी पहचान बढ़ाने में निरंतर प्रयासरत है, गर्व से प्रस्तुत करता है: ओलंपिक्स का मार्गः वीर प्रयासों की कहानी। यह प्रतिष्ठित आयोजन फाउंडेशन की चल रही पहल, रेडियंट इन क्वेस्ट ऑफ गोल्ड का हिस्सा है, जिसे 2017 में पैराथलीट्स को सशक्त बनाने और उन्हें श्रद्धा (Faith) और सबुरी (Patience) के सिद्धांतों पर चलने वाले भक्तों और प्रभावशाली व्यक्तियों से जोड़ने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था।

यह कार्यक्रम भारतीय पैराथलीट्स की अविश्वसनीय यात्रा को उजागर करेगा, जिन्होंने अपनी सफलता की ओर बढ़ते हुए अद्भुत बाधाओं को पार किया, और अंततः 2024 पेरिस पैरालंपिक्स में विजय प्राप्त की। यह आयोजन उनकी जीत का सम्मान करने के साथ-साथ उनके संघर्ष, दृढ़ता और शिर्डी साईं बाबा फाउंडेशन के अटूट समर्थन की कहानियों को साझा करने का **क** अवसर भी है।

एक अवसर भा ह।
आयोजन की मुख्य बातेंः शीर्षकः
ओलंपिक्स का मार्गः रेडियंट इन क्वेस्ट
ऑफ गोल्ड – एक शिर्डी साईं बाबा

इस कार्यक्रम में भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित पैराथलीट्स शामिल हुए, जिनमें शामिल हैं: सिमरन शर्मा - कांस्य पदक विजेता, पेरिस पैरालंपिक्स 2024

,योगेश कथुनिया - रजत पदक विजेता, पेरिस पैरालंपिक्स 2024,सुंदर सिंह गुर्जर - कांस्य पदक विजेता, पेरिस पैरालंपिक्स 2024,अशोक मिलक - कांस्य पदक विजेता, एशियाई खेल 2022, प्रवीण कुमार - स्वर्ण पदक विजेता, पेरिस पैरालंपिक्स 2024, रूबीना फ्रांसिस - कांस्य पदक विजेता, पेरिस पैरालंपिक्स 2024,मिरयप्पन थंगवेलु - कांस्य पदक विजेता, पेरिस पैरालंपिक्स 2024,धरमबीर - स्वर्ण पदक विजेता, पेरिस पैरालंपिक्स 2024,धरमबीर - स्वर्ण पदक विजेता, पेरिस पैरालंपिक्स 2024,गौरव खन्ना - राष्ट्रीय कोच, पैरा खेरा खेरा विजेता, पेरिस पैरालंपिक्स 2024,गौरव खन्ना - राष्ट्रीय कोच, पैरा

बैडिमंटन इंडिया, सत्य नारायण - अध्यक्ष, पीसीआई, एनसीपी प्रमुख ,औशिम खेतरपाल - शिर्डी साईं बाबा फाउंडेशन के संस्थापक, भारत के मान्यता प्राप्त सम्मानित अध्यक्ष ,राधिका खेतरपाल - अभिनेत्री, निर्देशक, ओटीटी निर्माता, रेडियंट डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स की अध्यक्ष

इस अनोखे आयोजन में शिर्डी साईं बाबा

फाउंडेशन के उन सतत प्रयासों को भी उजागर किया गया जो पैराथलीट्स के लिए प्रभावशाली प्लेटफॉर्म बनाने में लगे हैं, जैसे कि टेलीविजन शो ₹We the Change₹ और ₹Morpheous Dare To Dream Mission Made Possible₹, और उत्सव के आयोजन जैसे कि रेडियंट डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्स और क्रिकेट अवार्ड्स। इन पहलों ने फाउंडेशन की स्थापना से ही विकलांग खेल समुदाय के लिए अत्यधिक पहचान और समर्थन का सजन किया है।

सृजनाकया है। रेडियंट इन क्वेस्ट ऑफ गोल्ड का उद्देश्य पैराथलीट्स को आध्यात्मिक मार्गदर्शन, अधिक पहचान, और श्रद्धा (Faith) और सबुरी (Patience) के सिद्धांतों पर चलने वाले प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ जुड़ने के अवसर प्रदान करना है। इस कार्यक्रम ने खिलाड़ियों को मानसिक और शारीरिक रूप से अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रेरित

किया है। शिर्डी साईं बाबा फाउंडेशन के संस्थापक औशिम खेतरपाल ने इस पहल और इसके खिलाडियों के जीवन पर प्रभाव के बारे में

र अपनी गविंत भावनाएं व्यक्त कीः रेरेडियंट इन क्वेस्ट ऑफ गोल्ड के माध्यम से हमने खिलाड़ियों को सिर्फ जीत की ओर ही नहीं बल्कि आंतरिक शांति और शक्ति की

ही नहीं बल्कि आंतरिक शांति और शक्ति की ओर भी मार्गदर्शन किया है। पैरालंपिक्स की हर यात्रा खिलाड़ियों की दृढ़ता और संघर्ष की कहानी है। हमें उनके मार्ग का हिस्सा बनने पर गर्व है, और हम साईं बाबा की शिक्षाओं – धैर्य, विश्वास और दृढ़ संकल्प – के प्रतिबंब के रूप में उनकी सफलता का जश्न मनाने पर गर्व महसूस कर रहे हैं।₹
रेडियंट इन क्वेस्ट ऑफ गोल्ड के अलावा,
शिर्डी साईं बाबा फाउंडेशन कई अन्य महान
उद्देश्यों का भी समर्थन करता है, जिनमें
शामिल हैं:साईं प्रचार – शिर्डी साईं बाबा की
शिक्षाओं का प्रचार करना, पुस्तकों,
ऑडियो, फिल्मों, वीडियो और डिजिटल
कार्यक्रमों के माध्यम से।किन्नर सेवा –
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए रोजगार के
अवसर प्रदान करना ताकि सडक किनारे

भीख मांगने की प्रथा समाप्त हो सके और समाज में उनकी स्वीकार्यता बढ़ सके। गौ सेवा – दूध न देने वाले और परित्यक्त या घायल गायों और जानवरों को आश्रय और देखभाल प्रदान करना। क्लैरवॉयन्स के माध्यम से मार्गदर्शन और उपचार – औशिम खेतरपाल की दिव्य दृष्टि क्षमताओं के माध्यम से आध्यात्मिक मार्गदर्शन और उत्तर प्रदान करना।

प्रदान करना। शिर्डी साईं बाबा फाउंडेशन अपनी मिशन को जारी रखते हुए एक समान और सशक्त समाज का निर्माण करने के लिए प्रयासरत है। रेडियंट इन क्वेस्ट ऑफ गोल्ड, कई पैराथलीट्स के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक है। यह पहल न केवल उन्हें उनके पेशेवर और आध्यात्मिक विकास में समर्थन देती है, बल्कि उनके संघर्ष और उपलब्धियों की कहानियों के माध्यम से असंख्य अन्य लोगों को भी प्रेरित करती है।

हम सभी को आमंत्रित करते हैं कि वे इन खिलाड़ियों की अद्भुत उपलब्धियों और रेडियंट इन क्वेस्ट ऑफ गोल्ड की जारी यात्रा का में हमारे साथ शामिल हों।

समय की मांग, हिंदुओं को शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण होना होगा - नीरज दोनेरिया

स्वतंत्र सिंह भुल्लर

नई दिल्ली । विजयादशमी के पावन अवसर पर अनेक संगठनों द्वारा देश भर में शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अंबेडकर जिला दक्षिण प्रखंड ने दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार स्थित सांगवान बारात घर में शस्त्र पूजा कार्यक्रम आयोजित किया।

इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पधारे नीरज दोनेरिया (राष्ट्रीय संयोजक, बजरंग दल) ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा समाज लगातार बदल रहा है। समाज के इस बदलाव के साथ-साथ हमें भी अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। विश्व हिंदू परिषद बीते कई सालों से हिंदुओं को एकत्रित करने की कोशिश कर रहा है। हम सब हिंदुओं को एक साथ रहना होगा। आज हिंदुओं के स्वाभिमान में कमी आ रही है इस कमी को हमें खत्म करना होगा। हमें एक बात ध्यान देनी होगी अगर हिंदु



सुरक्षित होगा तभी भारत सुरक्षित रहेगा। हमारे देश में ही अनेक लोग रह रहे हैं जो देश के लिए अनेक प्रकार के खतरे खड़े कर रहे हैं। इस प्रकार के लोगों का हमें सामना करना होगा और देश की एकता और अखंडता के लिए इनको समाज के सामने उजागर करना होगा। हिंदुओं की संस्कृति में सबको एक साथ रहने का मंत्र दिया गया है। हिंदुओं का स्वभाव ही है सबको अपना मानना पर कई बार लोग इसे हिंदुओं की कमजोरी समझ लेते हैं। हमारे देश को स्वतंत्रता मिले अनेक साल हो गए हैं पर हम मानसिक रूप से अभी भी प्रशासनिक गुलामी को झेल रहे हैं। हम हमेशा यह सोचते हैं कि कोई भी काम करेगी तो सरकार करेगी। बहुत सारे कार्य हमें अपने बल पर ही करने होते हैं। हमें सुरक्षा का धर्म अपने ऊपर ही लेना होगा हमें अपने परिवार और अपने समाज की सुरक्षा स्वयं ही करनी होगी। हमें इसके लिए प्रशासन पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नन्द किशोर (दिल्ली प्रान्त संरक्षक, विश्व हिन्दू परिषद) ने कहा शस्त्र पूजन का कार्यक्रम हमें हमारी गौरवशाली संस्कृति से जोड़ने

का कार्य करता है। शास्त्र और शस्त्र आज समय की आवश्यकता है। इस मौके पर कुलदीप चौहान (प्रान्त सह संयोजक) प्रेम राज (प्रान्त धर्माचार्य संपर्क टोली)

महंत जी (अस्थल मंदिर) राहुल (विभाग संयोजक) कृष्ण मुरारी (अम्बेडकर जिला उपाध्यक्ष) अंकुश यादव (अम्बेडकर जिला मंत्री)नवीन (अम्बेडकर जिला संयोजक) हरिन्दर (सेवा प्रमुख) जितेंदर (सत्संग प्रमुख) स्वतंत्र सिंह भुल्लर (प्रचार प्रसार प्रमुख) व महेश खैरालिया सह मंत्री दक्षिणपुरी प्रखंड कृष्ण नैनावत चालीसा प्रमुख दक्षिणपुरी प्रखंड के अलावा भारी संख्या में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता व अन्य लोग मौजूद रहें।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क: 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No:- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023